खबर छुपेगी नहीं छपेगी

दुर्गमि ख़बर

राष्ट्रीय राजधानी से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष : 17 अंक 12 | दिल्ली, शनिवार 27 जुलाई 2024 | RNI-No. DELHIN/2008/2623 | पेजः 8 मूल्य : 1 रुपया

किसान, मैकेनिक, कुली और अब मोची बने राहुल गांधी

पेशी पर सुल्तानपुर पहुंचे कांग्रेस नेता ने मोची से की बातचीत

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पेश हुए। सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ वापस लौट रहे थे। इस दौरान जब उनका काफिला कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो चारों तरफ हलचल मच गई। अचनाक उनका काफिला चैत राम मोची की दुकान के पास रुक गया। दुकान पर राहुल गांधी पुराने जूते को ठीक करते दिखे। मोची से बातचीत की। वहां पांच मिनट रुककर राहुल ने उनसे व्यापार के बारे में बातचीत की, सेल्फी लिया। इसके बाद उनका काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए निकल गया। रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट रूम 16 मिनट रुककर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया उसके बाद उनका काफिला वापस लखनऊ के लिए चल पड़ा। राहुल को पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ एयरपोर्ट जाना था। राहुल गांधी का काफिला सुल्तानपुर से करीब 13 किमी दूर कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो उन्होंने बाए हाथ पर मोची की दुकान देखते ही गाड़ी रुकवाया और उतर कर सीधे चैत राम मोची के पास पहुंचे। राहुल गांधी का काफिला रुकते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ आसपस जमा हो गई। चैत राम की गुमटी पर वे पांच मिनट रुके। बातचीत की।

सेल्फी ली और फिर गंतव्य के लिए रवाना हो गए। चैत राम मोची ने बताया कि जिस जूते को हम सिल रहे थे, राहुल ने उसे छू कर देखा। उन्होंने पूछा कि कैसे बनाते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि घर का भरण-पोषण कैसे चलता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात पर मोची चेत राम ने खुशी जताई।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली के बाद अब हरियाणा पर 'एएपी' की है नजर

चंडीगढ़ (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए चुनाव प्रचार अभियान का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ

प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां करने जा रही है। आम आदमी पार्टी 15 दिनों में हर दो विधानसभा में एक चुनावी रैली करेगी। जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) डॉ. संदीप पाठक और प्रदेश की पूरी लीडरशिप इस अभियान में शामिल होगी।

पाकिस्तानी सेना की जेल भेजे जा सकते हैं इमरान

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात का अंदेशा है कि उनको जेल से निकालकर आर्मी के हवाले किया जा सकता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान पीटीआई नेता इमरान खान ने

लाहौर हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनको 9 मई की हिंसा के मामले में सैन्य हिरासत में सौंपे जाने की संभावना है। ऐसे में कोर्ट इस पर ध्यान दे और ऐसी किसी कोशिश को रोके। उन्होंने कहा कि बंदियों को नागरिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इमरान खान के वकील उजैर करामत ने लाहौर हाईकोर्ट में उनकी ओर से ये अर्जी दाखिल की है।

ओलंपिक से पहले फ्रांस के रेलवे नेटवर्क पर हमला

- पेरिस जाने वाली 3 हाईस्पीड रेलवे लाइनों पर आगजनी-तोड़फोड़

पेरिस (एजेंसी)। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार को पेरिस में ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ है। पेरिस के समयानुसार, सुबह 5.15 मिनट पर कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस से आने-जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर

दिया गया है। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही हैं। हमले की वजह से करीब 8 लाख यात्री स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। फ्रांस के सरकारी रेलवे कंपनी ने सभी पैसेंजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें स्टेशन न जाने की सलाह दी गई है। कंपनी ने अपने सैकड़ों कर्मियों को ट्रेन व्यवस्था दुरुस्त करने के काम पर लगा दिया है। वहीं हमले को देखते हुए ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

अग्निवीर योजना पर

विपक्ष झूठ फैला रहा

इसका मकसद सेना को युवा बनाना

करगिल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, खड़गे ने कहा-पीएम फिर झूठ बोल रहे

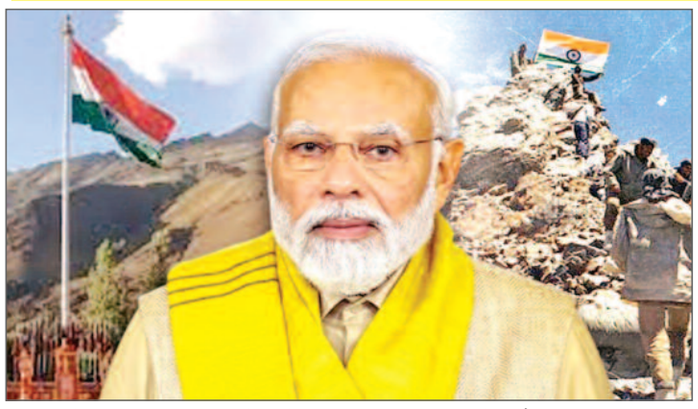

करगिल (एजेंसी)। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा- डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए। इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है। लेकिन हमने इस पर काम किया। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा-मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निपथ योजना लागू की। यह झूठ है। यह सेना का अपमान है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम मोदी कारगिल विजय दिवस के मौके पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पूर्व आर्मी चीफ (रिटायर्ड) जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 सालों की सेवा के बाद 75 फीसदी सैनिकों को रखा जाएगा और 25 फीसदी रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने इससे उल्टा किया है। योजना को तीनों सेनाओं पर जबरदस्ती लागू किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा- भारत कारगिल युद्ध से पहले शांति के प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सच के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी लेकिन उसने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं, जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है।

भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले

- राजस्थान में मदन राठौर और बिहार में दिलीप कुमार को मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान और बिहार के लिए भाजपा ने गुरुवार की देर रात नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को बिहार भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले यह जिम्मा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास थी। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद मदन राठौर को पार्टी ने राजस्थान का चीफ बनाया है। इससे पहले लोकसभा सांसद सीपी जोशी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे। 24 जुलाई को ही उन्होंने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दिया था। इसके अलावा भाजपा ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों को बदला है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नामों की घोषणा की।

बंगाल को बांटना चाहते हैं...

नीति आयोग की बैठक से पहले ममता के तल्ख तेवर

- बोलीं-मैं करूंगी विरोध, दिल्ली रवाना होने से पहले बोला बड़ा हमला
- बंगाल बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर ममता बनर्जी का पलटवार

कोलकाता/नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में तृणमूल सांसदों के बजट के मुद्दे पर तीखे विरोध के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में

आ गई है। ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में मौजूद रहने क संकेत देते हुए कहा है कि मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। उनके मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं। आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ वे भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं। झारखंड, बिहार और बंगाल को बांटने के लिए अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए मैं वहां मौजूद रहूंगी। ममता ने पश्चिम बंगाल की अनदेखी का आरोप लगाया।

झमाझम बारिश से बेहाल हुए महाराष्ट्र और गुजरात

- महाराष्ट्र के पुणे में 57 साल बाद 114 एमएम बारिश
- गुजरात के 10 जिलों में बाढ़, सूरत में 1 लाख लोग फंसे
- एमपी-यूपी और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सितम जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा और सांगली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। पुणे में 24 घंटे में 114 मिमी बारिश हुई। यह 66 साल में तीसरा हाईएस्ट रहा। इससे पहले 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिमी और 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में

परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उधर, गुजरात में तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। यहां 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सूरत में 24 घंटे में 5 इंच बारिश से मीठी और काकरा खाड़ी नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। यहां बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

वहीं, 955 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी भर गया। मुख्य मार्गों में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के मदमहेश्वर मंदिर के निकट भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 50 श्रद्धालु और स्थानीय लोग फंस गए। मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार मंदिर समूह का हिस्सा है और 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मौसम विभाग ने आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सतना में 9 घंटे में 88 मिमी, तो रतलाम में 80 मिमी बारिश हो गई। टीकमगढ़ में धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से 24 जुलाई की रात बान सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोलकर 480 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ललितपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। गोविंद सागर बांध के 16 गेट खोल दिए गए।

विधायकों से मीटिंग कर लिया यूपी हार का 'फीडबैक'

पूरा 'होमवर्क' कर मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे सीएम योगी

योगी ने विधायकों से लिया फीडबैक और मंडलवार की बैठक

लखनऊ (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। बीते कुछ दिनों से सरकार से लेकर भाजपा संगठन तक में तमाम तरह की घटनाओं को देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म रहा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दिल्ली होकर भी आ गए।

इस बीच उनके बागी तेवर वाले बयान भी चर्चा में रहे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा भाजपा की संगठन बैठक में भी हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले योगी उत्तर प्रदेश में मंडलवार विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। योगी के अलावा, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और बृजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये सभी लोग संगठन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद ऐसे कयास लगने तेज हो गए हैं कि लोकसभा में हार के बाद बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्दी ही कोई बड़ा फैसला

आ सकता है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर असंतोष की अटकलें सामने आने लगी थीं।

योगी बोले-

जनप्रतिनिधियों हर बात सुनी जाएगी- प्रदेश के अफसरों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात सर्वोपरि है। वह हर स्तर पर सुनी जाएगी। शासन से लेकर जिलों के अफसरों तक को इसके साफ निर्देश हैं। सभी को सकारात्मक सोच व छवि के साथ मिलकर काम करना होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगातार प्रदेश नेतृत्व सवालों के घेरे में था। योगी आदित्यनाथ पर इस बात को लेकर दवाब था कि उनकी ही पार्टी के विधायक और मंत्री प्रदेश के अधिकारियों की मनमानी को लेकर शिकायत कर रहे थे। ऐसे में योगी के खिलाफ पार्टी के विधायकों में असंतोष की भी बातें चल रही थीं। केशव प्रसाद मौर्य के स्वर इस दौरान सबसे ज्यादा मुखर रहे। इस बीच शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली जाना था। योगी ने इससे पहले प्रदेश के विधायकों से फीडबैक लिया और मंडलवार बैठक कर उनकी बातें सुनीं और सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन भी दिया। माना जा रहा है कि योगी यहां पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।

हरियाणा पहुंचे सीएम भगवंत: बरवाला रैली में भरी विधानसभा चुनाव की हुंकार, कहा- इन गारंटियों को किया जाएगा लागू

हिसार (हरियाणा) : आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को हिसार में चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बरवाला की अनाज मंडी में आयोजित रैली को संबोधित किया। उनके साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पांच गारंटी देगी। सीएम मान ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद दिल्ली व पंजाब की तरह से इन गारंटी को लागू किया जाएगा। बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए हरियाणा के लिए पांच गारंटियां भेजी हैं और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने हाल ही में ये प्रदेश को समर्पित की हैं। पार्टी की पांच गारंटियों में 24 घंटे बिजली, गरीबों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस सेवा, 1000 महीना की सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने की गारंटी शामिल है।

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में देगी रियायत

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपोज़िट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। शुक्रवार को एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, इस क़दम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद, नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी। नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोज़िट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद-फरोख्त किया जा सकता है।

केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर 'इंडिया' गठबंधन की रैली, आप ने साधा भाजपा पर निशाना

नई दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खराब हो रही सेहत का मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक रैली करेगा। आम आदमी पार्टी (आप) ने यह जानकारी दी। 'आप' भाजपा (भाजपा) पर केजरीवाल को जेल में जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि तीन जून से सात जुलाई के बीच उनका शर्करा स्तर 26 बार कम हुआ। 'इंडिया' की घटक दल 'आप' ने भाजपा नीत केंद्र सरकार और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर केजरीवाल के जीवन से खेलने का आरोप लगाया। आप ने कहा, 'केजरीवाल की खराब हो रही सेहत का मुद्दा उठाने के लिए 'इंडिया' 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर बड़ी रैली करेगा।'' संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब आतिशी से रैली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया, ''भाजपा हर तरीके से दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजिश रच रही है। भाजपा दिल्ली के लोगों के कार्यों को रोक रही है। यह दिल्ली के लोगों के पैसों को रोक रही है। भाजपा ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कराया।'' आतिशी ने दावा किया कि जब भाजपा को पता चला कि केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल सकती है तो उसने मुख्यमंत्री को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से गिरफ्तार करा दिया। उन्होंने कहा, ''उन्हें (भाजपा को) पता था कि केजरीवाल को पिछले 30 वर्ष से मधुमेह है। उनका वजन हिरासत में रहने के दौरान साढ़े आठ किलोग्राम तक कम हो गया। एक ग्लूकोमीटर से पूरे दिन उनके शर्करा स्तर पर नजर रखा जाता है। इस उपकरण का डेटा उपराज्यपाल और केंद्र के साथ साझा किया जाता है। उन्हें पता है कि केजरीवाल का शर्करा स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है।'' आतिशी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का शर्करा का स्तर 34 बार घटा है। उन्होंने कहा, ''भाजपा चाहती है कि उनका (केजरीवाल का) स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब हो जाए। 'इंडिया' गठबंधन की सभी पार्टियां केजरीवाल की हिरासत और उनके स्वास्थ्य को खतरा पैदा किये जाने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी।'' केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई है। हालांकि, वह वर्तमान में सीबीआई के एक मामले में तिहाड़ जेल में हैं।

रिज क्षेत्र में जमकर बरसे बदरा, नजफगढ़-नरेला सूखे रहे

नई दिल्ली। राजधानी में एक बार फिर मानसून का अजीब रुख देखने को मिला। शुक्रवार सुबह रिज और डीयू के आसपास भारी बारिश हुई, जबकि नजफगढ़ और नरेला जैसे इलाके सूखे रह गए। लोगों को बूंदाबांदी से संतोष करना पड़ा। दिल्ली में इस बार मानसून का रुख काफी उतार-चढ़ाव भरा देखने को मिल रहा है। किसी हिस्से में तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लोग जलभराव और जाम से परेशान हैं, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी भी मुश्किल से हो रही है। शुक्रवार को रिज क्षेत्र में सुबह साढ़े आठ बजे तक 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के मानकों के मुताबिक, चौबीस घंटे के भीतर 64.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर उसे भारी बारिश माना जाता है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में भी मध्यम बारिश यानी 39.4 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन पालम मौसम केन्द्र में सिर्फ 0.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी तरह से नरेला और नजफगढ़ जैसे इलाकों में बेहद हल्की बूंदाबांदी हुई। आयानगर मौसम केन्द्र में भी सिर्प 7.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के चलते उमस भरी गर्मी से राहत - दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो-दो डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 100 से 77 फीसदी तक रहा। तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से खासी राहत मिली। दूसरी ओर, मौसम की इन गतिविधियों के चलते दिल्ली की हवा भी काफी हद तक साफ हो गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।

निगम स्कूलों की कमियों को दूर कर रिपोर्ट दाखिल करें : हाईकोर्ट

नई दिल्ली,। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों का दौरा कर सुधारात्मक कदमों के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक रिपोर्ट में स्कूल की कमियों को उजागर होने के बाद यह आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूलों में टूटी हुई डेस्क, कुर्सियां, शिक्षकों की कमी और कक्षाओं में पानी भरने से काफी परेशानी होती है। पीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छात्रों को 15 अगस्त तक उनकी वर्दी मिल जाए और स्कूलों में कुर्सियां और डेस्क उपलब्ध करा दिए जाएं। याचिकाकर्ता एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, कड़कड़डूमा और खजूरी चौक में एमसीडी प्राथमिक स्कूलों के अपने दौरे के संबंध में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे खराब परिस्थितियों में चल रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में 1.37 लाख से अधिक छात्रों को अभी तक वर्दी नहीं मिली है। पीठ ने कहा कि एमसीडी को निर्देश दिया जाता है कि 1.37 लाख छात्रों को जितनी जल्दी हो सके वर्दी या नकद राशि हस्तांतरित की जाए। शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि छात्रों को जल्द से जल्द डेस्क और कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएं। एमसीडी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि डेस्क की आपूर्ति की जाएगी और वर्दी की आपूर्ति न होने के मुद्दे का भी हल किया जाएगा।

स्कूल में भरे पानी का वीडियो चलाया गया

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने आजादपुर स्थित लालबाग के निगम स्कूल में आज सुबह की बारिश के बाद की स्थिति बयां की। पीठ के आदेश पर इस स्कूल का वीडियो कोर्ट रूम में चलाया गया। स्कूल में पानी भरा था। बच्चे भी वहां मौजूद थे। पीठ ने इस पर निगम को कड़ी फटकार लगाई है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खिचड़ीपुर में कावड़ शिविर का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने शिव भक्त कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा खिचड़ीपुर में 'खिचड़ीपुर शिव कांवड़ सेवा समिति' शिविर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरी दिल्ली में करीब 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने सभी जिला प्रशासन को कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर जरूरी कदम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से हर वर्ष भगवान भोलेनाथ के भक्त और कावड़ियों के लिए शिविर कैंप लगाए जाते हैं। यह शिविर कैंप पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। इसके अलावा इन कैंपों के अंदर मेडिकल से लेकर पानी, सोने के लिए बेड, कूलर और शौचालय की समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरोलिया, कल्याणपुरी से पार्षद बंटी गौतम, समिति के अध्यक्ष सुरज मल वर्मा, विश्वास नगर विधानसभा के अध्यक्ष दीपक सिंगला, सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम भट्ट समेत अन्य लोग मौजूद थे। सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जल लेने जाते हैं। इसके बाद लोग अपने-अपने शहर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर दिल्ली सरकार राजधानी में जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाती है। कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के रुकने और आराम करने के लिए हर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। इस साल उनकी सुविधा के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा गया है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए कैट्स एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पतालों को कांवड़ियों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपाल राय ने आगे कहा कि चूंकि बारिश की अधिक संभावना है। इसलिए बिस्तर और मेजों के साथ वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगे बताया कि 185 शिविरों में कम से कम 10 हजार श्रद्धालु आसानी से रह सकते हैं। सावन में बारिश की अच्छी संभावना है, इसलिए हमने शिविर में वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की है। साथ ही यहां डॉक्टर को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, मेडिकल टीमें 24 घंटे शिविर में मौजूद रहेंगी और तीन अलग-अलग शिफ्टों में काम करेंगी। कावड़ शिविर के बाहर एंबुलेंस भी तैनात की गई है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य चोट की स्थिति में, व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाया जाएगा।

अभाविप ने जेएनयू प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ

नई दिल्ली (एजेंसी)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रशासन को सकारात्मक दिशा में लाने के उद्देश्य से विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का आयोजन समर-भूमि (टी-पॉइंट) पर किया गया, जिसमें छात्रों ने पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में अभाविप के 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और जेएनयू प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की।

अभाविप के कार्यकर्ताओं ने यहां एक प्रेस वार्ता में अपनी तमाम मांगों के बारे में जानकारी दी। इनमें भ्रष्टाचारी जेएनयू प्रशासन पर लगाम लगाना, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (एसओई) की बिल्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) को जेएनयू में लागू करना, छात्रावास की समस्याएं, अकादमिक समस्याएँ, प्रशासनिक समस्याएँ, बुनियादी सुविधाओं की कमी, जिसमें स्वच्छ पेयजल, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएँ आदि प्रमुख मांगें हैं। अभाविप जेएनयू अध्यक्ष राजेश्वर कांत दूबे ने कहा, जब तक छात्रों की आवाज नहीं सुनी जाएगी और उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक मैं अपने सभी पद का त्याग कर छात्रों के साथ इस संघर्ष में डटा रहूंगा। आज हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ में प्रशासन की बुद्धि में शुद्धता आने की प्रार्थना की और जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह हमारा संकल्प है कि हम छात्रों के अधिकारों के लिए अंत तक लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को उचित सुविधाएँ मिलें और प्रशासन उनके प्रति संवेदनशील बने। हम सभी छात्रों को एकजुट कर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। अभाविप जेएनयू मंत्री शिखा स्वराज ने कहा, अभाविप का यह अनिश्चितकालीन धरना, जिसे हमने 'छात्र समर' का नाम दिया है, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए है। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और छात्रों को उनकी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल जातीं। हमारा यह आंदोलन छात्रों के हित में है और हम इसे सारी मांगें पूर्ण होने तक किसी भी हालत में समाप्त नहीं करेंगे।

आप नेता राघव चड्ढा ने संसद में केंद्र सरकार को घेरा, उठाया स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स का मुद्दा

नई दिल्ल। आम आदमी पार्टी (आप) नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज यानी शुक्रवार को संसद में 'स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स' का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के कई सदस्यों, पत्रकारों आदि को 'स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स' का नोटिफिकेशन आया है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और जिन लोगों पर यह अटैक हुआ है क्या उनकी कोई सूची बनाई गई है और क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ कार्यवाही की है? आम आदमी पार्टी आप नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि निवेशकों के 'इंडेक्सेशन' लाभ हटाना सरकार की गंभीर गलती है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि 'इंडेक्सेशन' का लाभ हटाना देश के निवेशकों के जेब पर डाका डालने के बराबर है। कहा कि सरकार ने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो रियल इस्टेट में निवेश में गिरावट होगी। राघव चड्ढा ने कहा कि इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया तो रियल इस्टेट में सेक्टर ब्लैक मनी आने की संभावना है। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है किंतु सेवाएं सोमालिया की जैसी मिलतीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में केंद्र सरकार ने टैक्स लगा लगाकर आम आदमी का खून चूसा है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत सरकार से संसद में एससी/एसटी समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में सवाल पूछा। सरकार की प्रतिक्रिया में सामने आए आंकड़े चिंताजनक हैं और 2018 के बाद से अपराधों में तेज वृद्धि दर्शाते हैं। पिछले छह वर्षों में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध 35त्न बढ़े हैं। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में 54त्न की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

युवा कांग्रेस ने बजट के विरोध में किया विशाल प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के सदस्यों ने शुक्रवार को बजट को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया और इसे 'कुर्सी बचाओ बजट' करार दिया। यह विरोध प्रदर्शन मध्य दिल्ली में शास्त्री भवन के पास आईवाईसी मुख्यालय में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों में से एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहना था और एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि अन्य ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। ढृड्ढष्ट अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश किया गया केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई राज्यों की अनदेखी की गई है।

श्रीनिवास ने कहा, 'यह मोदी जी का 'कुर्सी बचाओ', 'सत्ता बचाओ' और 'बदला लो' बजट है क्योंकि यह 90 प्रतिशत राज्यों और देश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी को अलग-थलग कर देता है।' उन्होंने कहा कि पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है लेकिन इस बजट में इसके खिलाफ कोई कदम उठाने की बात नहीं है।

विपक्ष ने गुरुवार को संसद में बजट चर्चा के दूसरे दिन बजटीय आवंटन को लेकर सरकार पर हमला जारी रखा और दावा किया कि यह एनडीए सहयोगियों के लिए आभार पत्र की तरह है, लेकिन भाजपा ने जोर देकर कहा कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और भारत को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

राहुल गांधी ने बजट को संघीय ढांचे की पवित्रता पर बताया था हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बजट की आलोचना करते हुए कहा था कि यह भारत के संघीय ढांचे की पवित्रता पर हमला है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ कथित भेदभाव को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था।

राहुल गांधी ने अपने वॉट्सऐप चैनल पर विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था, 'आज इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में एनडीए के 'कुर्सी बचाओ बजट' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।'

ऑनलाइन टास्क देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो जालसाज गिरफ्तार, महिला से ठगे थे 18 लाख रुपये

नई दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑनलाइन टास्क देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों गिरोह के मास्टरमाइंड को कमीशन पर बैंक खाते बेचते थे। दोनों को बंगलुरू से पकड़ा गया है। पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने बताया कि जालसाजों की पहचान बंगलुरू हरिनगर निवासी मोहम्मद अली और दीपू पी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनसे मोबाइल और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि यह दोनों संयुक्त बैंक खाते खोलते थे। फिर उन्हें वॉट्सऐप और टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को बेच देते थे। फिर गिरोह इन खातों का ठगी में इस्तेमाल करता था। दोनों आरोपितों को खाता बेचने पर हर महीने कमीशन मिलता था। दोनों के खिलाफ पूर्व में 40 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। 21 फरवरी को आरकेपुरम सेक्टर 10 निवासी नलिनी खन्ना नाम की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि वह फेसबुक पर एक लिंक पर क्लिक करने के बाद वॉट्सऐप ग्रुप पर जुड़ गई। यहां पर उन्हें ऑनलाइन टास्क देकर मोटी कमाई करने का झांसा दिया गया। आरोपितों ने शुरुआत में महिला को मुनाफा देकर भरोसे में लिया। इस पर महिला ने करीब 18 लाख रुपये का निवेश कर दिया। जब उसने अपने पैसे वापस निकालने का प्रयास किया तो वह सफल नहीं हुई। तब उन्हें ठगी का पता चला और शिकायत दी। इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ठगी की रकम तीन अलग अलग बैंक खातों में भेजी गई है। यह आरोपित दीपू पी मोहम्मद अली के नाम पर निकले। तब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। जालसाजों ने बताया कि उन्होंने कुल नौ खाते खुलवाए थे। फिर इन्हें व्हाट्सऐप के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को बेच दिया। आरोपितों को खातों के एवज में 1-10 लाख रुपये कमीशन के मिले थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कपड़ा उद्यमी को 'एडिडास' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोका

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक उद्योगपति को खेल के सामान एवं परिधान बनाने वाली दिग्गज कंपनी एडिडास एजी से मिलते-जुलते नाम वाले ब्रांड का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह उद्योगपति अपने कपड़ा उत्पादों के लिए 'एडिडास' ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर रहा था। उसने दलील दी थी कि वह अपनी बड़ी बहन के प्रति गहरी श्रद्धा दर्शाने के लिए एडिडास नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि बहन के प्रति स्नेह जताने के लिए एडिडास नाम को चुनने के दावे की पुष्टि करने वाले साक्ष्य नहीं हैं। ऐसे में जर्मन कंपनी के ट्रेडमार्क से भ्रामक रूप से मिलने वाले नाम का इस्तेमाल न किया जाए। प्रतिवादी केशव एच तुलसियानी ने दलील दी थी कि वह अपनी बड़ी बहन के प्रति गहरी श्रद्धा जताने के लिए एडिडास नाम का इस्तेमाल करना चाहता है। उसने कहा था कि सिंधी समुदाय में बड़ी बहन को 'आदि' कहा जाता है और वह खुद को उनका भक्त यानी 'दास' समझता है। उसका दावा था कि 'एडिडास' (एक बड़ी बहन का भक्त) शब्द की कल्पना 'आदि' (बड़ी बहन) और 'दास' (भक्त) को मिलाकर की गई थी, ताकि इस पारिवारिक भक्ति को स्नेह को दर्शाया जा सके। तुलसियानी एडिडास वीविंग मिल्स, एडिडास टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज और एडिडास मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार एवं निदेशक हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि 'एडिडास' जैसे विशिष्ट और मशहूर ट्रेडमार्क की नकल से उसकी विशिष्टता कम हो सकती है। ऐसे में प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के चिह्न का अनधिकृत उपयोग वादी की स्थापित प्रतिष्ठा और सद्भावना से लाभ उठाने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। एडिडास एजी की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है लिहाजा वादी स्थायी रोक का आदेश पाने की हकदार है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रतिवादी को किसी भी रूप में एडिडास चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करेगा : संदीप पाठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, 26 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आगामी 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन के घटक दल एक मंच पर नजर आएंगे। आप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और सांसद संदीप पाठक ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल को लंबे समय से शुगर है। शुगर बहुत गंभीर बीमारी है, जिसकी दो अवस्था है। एक में

शुगर बढ़ता है और दूसरे में यह घटता है। शुगर लेवल घटने को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। शुगर का बढ़ना समस्या है, लेकिन शुगर लेवल का घटना बहुत खतरनाक स्थिति होती है। शरीर में ग्लूकोज स्तर नीचे जाता है तो शख्स कोमा में जा सकता है। संदीप पाठक ने कहा कि तीन जून से सात जुलाई के बीच जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 34 बार शुगर लेवल 50 या इससे नीचे जा चुका है। यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की व्यवस्था का मामला है। अगर इसी तरह से राजनीति होगी तो कोई राजनीति में क्यों आएगा। आज यह प्रश्न अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश की व्यवस्था का है। 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचीं। ममता बनर्जी सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल ने ममता बनर्जी का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। यह पहली बार है जब ममता बनर्जी सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान सीएम केजरीवाल की माता-पिता से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी ने उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। बता दें, ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने आज ही दिल्ली पहुंची हैं।

वहीं मुलाकात के आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया- तानाशाह की तानाशाही के विरोध में एकजुट है 'इंडिया'। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मिलने उनके निवास पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने ममता बैनर्जी जी का किया स्वागत।

केजरीवाल का समर्थन करती रहीं हैं ममता

ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच संबंध काफी बेहतर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी ममता केजरीवाल को अपना समर्थन देती रही हैं। दोनों ने कई बार एक साथ मंच भी साझा किया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन के तमाम नेता सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचते रहे हैं।

उन्हें केजरीवाल के स्वास्थ्य की थी चिंता: राघव

मुलाकात के बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, 'पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और माता-पिता से मिलने उनके आवास पर गईं। उन्हें अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता थी। उन्होंने संदेश दिया कि संघर्ष की इस घड़ी में वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं।'

Punjab Land of Unlimited Opportunities

हर एक की हुई तरक्की

भगवंत सिंह मान की पंजाब सरकार की गारंटी पक्की

भगवंत सिंह मान
मुख्यमंत्री, पंजाब

एस.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तहत ₹ 225.60 करोड़ जारी

आशीर्वाद स्कीम के तहत 38,179 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ₹ 193.77 करोड़ जारी

- एस.सी. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2017-20 तक की बकाया राशि के लिए ₹366.00 करोड़ जारी
- एस.सी. विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, कुल ₹165.00 करोड़ की राशि जारी
- पिछड़े/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 18,510 लाभार्थियों को ₹94.22 करोड़ जारी
- स्व-रोज़गार योजनाओं के तहत 38 लाभार्थियों को ₹0.79 करोड़ का ऋण वितरित

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

कारगिल विजय दिवस के शहीदों को नमन

प्रेम कुमार धूमल

उस ऐतिहासिक क्षण में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन 'जब तक एक भी घुसपैठिया कारगिल में है, तब तक न युद्ध विराम होगा और न मैं देश छोड़कर कहीं जाऊंगा' इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । प्रधानमन्त्री के इस दृढ़संकल्प को देखते हुये सारे राष्ट्र में एक नई ऊर्जा आ गई और सैनिकों में यह संकल्प और दृढ़ हो गया और भारत की वीर सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की ।

देश में राष्ट्रभक्ति का गजब का माहौल था ऐसा लगता था सारा भारत एक है, देश की एकता, अखण्डता, सर्वभौमिकता बचाये रखने के लिये कुछ भी कर गुजरने को तैयार था । कारगिल का संघर्ष क्या शुरू हुआ ऐसा लगा जैसे सारा राष्ट्र और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक देष के लिये कोई भी कुबार्नी देने को तैयार था । विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ जब देशाभक्ति से ओत-प्रोत विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के प्रधानमन्त्री, अटल जी सभी चुनौतियों, चेतावनियों और व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरों को नजर अन्दाज करते हुये 2 जुलाई 1999 को सीमा पर तैनात युद्धरत सैनिकों की पीठ थपथपाने के लिये स्वयं सीमा पर जा पहुंचे । आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमन्त्री को अपने साथ सीमा पर खड़ा देखकर सैनिकों का साहस तो सातवें आसमान पर पहुंचना स्वभाविक था । 5 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद श्रीनगर के सैनिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल सैनिकों को दैनिक उपयोग का आवश्यक सामान दे रहे थे, एक जवान चादर ओढ़े हुये लेटा था उसने सामान पकड़ा नहीं, हमने विस्तर के साईड टेबल पर सामान रखा और आगे बढ़ने लगे तभी डॉक्टर ने कहा कि माईन ब्लास्ट में इस वीर सैनिक के दोनों हाथ और दोनों पैर चले गये थे । हम फिर मुड़े और पूछा, 'बहुत दर्द होता होगा', सैनिक ने उतर दिया, 'कल शाम से नहीं हो रहा है' । हमने पूछा क्या कोई (पेन किलर) दर्द निवारक दवाई ली या टीका लगा ? उसने उतर दिया ह्यह्यनहीं, कल शाम (4 जुलाई को) टाईगर हिल वापस ले लिया और तिरंगा फहरा दिया, मेरा दर्द चला गया । राष्टभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को शत शत नमन ।

आजकल एक और विवाद मीडिया में देखने को मिला यहां शहीद की नौजवान विधवा ने मरणोपरान्त मिलने वाले सम्मान को शहीद के मॉ-बाप के साथ सांझा करना उचित नहीं समझा। ऐसी समस्यायें आप्रेशन विजय के बाद भी आई थीं, अधिकतर विधवायें नवविवाहिता थीं और उनका पुनर्विवाह होना स्वभाविक और न्यायोचित भी था परन्तु बजुर्ग मॉ-बाप का सहारा भी तो शहीद जवान ही होता था इसलिये पुनर्विवाह के समय प्रदेश और केन्द्र सरकार की ओर से मिली सारी की सारी अनुदान राषि, पैट्रोल पम्प या गैस एजैन्सी आदि सभी को साथ ले जाना मॉ-बाप के साथ अन्याय था क्योंकि अधिकतर मामलों में गरीब मॉ-बाप ने अपना पेट काट कर बेटे को पाला पोसा होता था और बुढ़ापे में नौजवान बेटे की शहादत और बहु का सब कुछ

अपने साथ ले जाना उनके लिये दोहरा अघात होता था। इसलिये हमने प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया कि अगर तो पुनर्विवाह उसी परिवार में होता है तो सभी कुछ वैसे ही रहेगा लेकिन यदि वीर नारी कहीं दूसरी जगह शादी करती है तो सरकार की ओर से मिली राषि दो हिस्सों बांट दी जायेगी । आधी राषि उस युद्ध विधवा को और आधी राषि बूढ़े मॉ-बाप को दी जायेगी और यदि शहीद के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और मॉ तथा दादा-दादी से अलग रहते हों तो राषि तीन भागों में बांटी जायेगी और एक तिहाई बच्चों को दी जायेगी। इस निर्णय से सभी की समस्या का समाधान हो गया ।

राष्ट्रभक्ति के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्बेदनशीलता के भी कई उदाहरण देखने को मिले, शामिला जिले का एक अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाला जवान शहीद हुआ था, घर की अर्थिक स्थिति भी कमजोर थी । जब हमने अनुग्रह राषि उन्हें दी तो उस गरीब परिवार ने कहा हमें आधी राषि ही दीजिए, अभी युद्ध चल रहा है और शहीद हो रहे हैं और आपको कई और परिवारों की सहायता करनी है, हमें आधी राशी दे दो बाकि किसी और परिवार के काम आ जायेगी । शहीद की शहादत को तो नमन था ही पर गरीब परिवार की सम्बेदनशीलता और दूसरों के प्रति समर्पण की भावना से हम सभी द्रवित हो गये और उन्हें धन्यवाद देते हुये हमने कहा कि राषि आपके लिये ही है और आवश्यकता होगी तो लोग योगदान दे ही रहे हैं ।

पालमपुर में तो जहां एक ओर प्रथम परमवीर चक्र विजेता, मेजर सोमनाथ शर्मा वहीं कारगिल युद्व के नायक कै. विक्रम बतरा, परमवीर चक्र विजेता का भी घर है, उस दिन हम कै. विक्रम बतरा के पार्थिव शरीर का इन्तजार कर रहे थे वहीं पर कारगिल युद्व के प्रथम शहीद कै. सौरभ कालिया की माता जी, विजय कालिया और कै. विक्रम बतरा की माता जी साथ साथ बैठी थीं । विजय कालिया श्रीमति बतरा को ढांढस बंधा रही थीं, एक महान मां दूसरी महान माता को साहस बंधा रही थी, शायद यही जीवन है।

इसी प्रकार जिला बिलासपुर की एक बहादुर मां, कौषल्या देवी जी जब मिली तो अन्होंने कहा, 'धूमल जी कल मंगल सिंह की अर्थी को डेढ किलो मीटर मैंने कंधा दिया'। मैंने पहली बार सुना कि शहीद की मॉ ने अपने शहीद सुपुत्र की अर्थी को कंधा दिया हो । शहीद की शहादत और मॉ की हिम्मत को सलाम ।

सोलन जिला मुख्यालय में चपरासी के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति का सैनिक बेटा शहीद हो गया, अन्तिम संस्कार में भाग लेने के बाद हम उसके घर ढांढस बंधाने के लिये गये। शहीद की मॉ ने कहा मेरा बेटा देश के काम आ गया, दूसरा बेटा दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है यह भी पढ़कर फौज में भर्ती होगा और देश की सेवा करेगा।

जिला हमीरपुर के बमसन क्षेत्र में पहाड़ी के ऊपर एक बगलू गांव है यहां से राज कुमार सुपुत्र खजान सिंह शहीद हुये थे। चढ़ाई चढ़ते मैं सोच रहा था कि शहीद के बजुर्ग पिता जी से कैसे बात करूंगा । मैं उनके आंगन में पहुंच गया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, खजान सिंह बोले, 'धूमल साहब, बेटे तो पैदा ही इसलिये किये जाते हैं कि पढ़ें, लिखें और बड़े होकर फौज में भर्ती हों और देश की रक्षा करें । उन्होंने अपने दोनो पोते मुझे मिलाये और कहा ये भी पढ़कर फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे । उन्होंने मुझे कहा आप दिल्ली जायेंगे तो प्रधानमन्त्री, वाजपेयी जी को कहना कि जवानों की यदि कमी हो तो 82 वर्ष का हबलदार खजान सिंह आज भी हथियार उठाकर देष की रक्षा करने के लिये तैयार है ।

शहीदों का आदम्य साहस, परिवारों का सम्पूर्ण समर्पण, अटल जी का दृढ़निष्चयी नेतृत्व सदियों तक देष के लिये प्रेरणा रहेगा ।

5 जुलाई को जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आदरणीय अटल जी को फोन करके कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ इनके पास पहुंच गये हैं और अटल जी से आग्रह किया कि वे भी युद्व विराम की घोषणा कर दें और अमेरिका आ जायें ताकि समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जा सके ।

उस ऐतिहासिक क्षण में श्रद्वेय अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन 'जब तक एक भी घुसपैठिया कारगिल में है, तब तक न युद्व विराम होगा और न मैं देश छोड़कर कहीं जाऊंगा' इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ।

प्रधानमन्त्री के इस दृढ़संकल्प को देखते हुये सारे राष्ट्र में एक नई ऊर्जा आ गई और सैनिकों में यह संकल्प और दृढ़ हो गया और भारत की वीर सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की ।

कारगिल से वापसी पर हम प्रभु अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास उतरे, दर्षन किये और संयोग से टाईगर हिल विजय प्राप्त करने वाले जवान भी उसी समय गुफा में दर्षन करने के लिये आये हमने उन से चर्चा की और नरेन्द्र मोदी जी ने तो उनके हथियार लेकर उन हथियारों के बारे में जानकारी भी ली ।

यह उचित ही है कि 26 जुलाई को प्रतिवर्ष हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और उन शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित करते हैं । ठीक ही कहा है 'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशां होगा'।

-(लेखक हिमाचल के पूर्व मुख्यमन्त्री रहे हैं व कारगिल युद्व के समय मुख्यमन्त्री थे।)

संपादकीय

अनावश्यक फैसला

भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा और विवादों के केंद्र में रहा है। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगे करीब छह दशक पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है जिसे बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कि राजनीतिक क्षेत्रों में इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्मचारियों को वैचारिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। वस्तुतः आरएसएस की चाहे जितनी आलोचना या निंदा की जाए लेकिन राष्ट्र के उत्थान में इस संगठन की सार्थक भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार में भी 1932 में सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन इस प्रतिबंध के कारण आरएसएस के विस्तार में रुकावट नहीं आई। यह संगठन अपने ध्येय को लेकर आगे बढ़त्ता गया। आरएसएस अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और अब यह संगठन समाज की मुख्यधारा में है। आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या, आपातकाल और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद इस संगठन से जुड़े.हुए लोग आज देश के शीर्ष पदों पर आसीन हैं। कुछ लोग संघ और सरकार के बीच संबंधों की तुलना चर्च और राज्य के रिश्ते से करते हैं। उनका विश्वास है कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में चर्च और राज्य के बीच विभाजन रेखा का सम्मान किया जाता है लेकिन आरएसएस दावा करता है कि वह सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है और राजनीति एवं धर्म से इसका दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। आरएसएस पर ब्रिटिश सरकार से लेकर आज तक हमले होते रहे हैं लेकिन अपनी स्थापना के सौ वर्षों में यह संगठन बरगद का रूप ले चुका है। पूर्वोत्तर भारत यदि देश की मुख्यधारा में शामिल हुआ है तो इसका श्रेय आरएसएस को ही दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस का द्वार खोलने का केंद्र सरकार का फैसला एक नये विवाद को जन्म देने वाला है। संघ को इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

चिंतन-मनन

सत्ता-संपदा का उन्माद

मनुष्य विचारशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। उसके पास बुद्धि है, शक्ति है। वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, चिंतन के हर कोण पर रुकता है, विवेक को जगाता है, शक्ति का नियोजन करता है और संसार के अन्य प्राणियों से बेहतर जीवन जीता है। जीने के लिए वह अनेक प्रकार की सुविधाओं को जुटाता है। सत्ता और संपदा ये तो ऐसे तत्व हैं, जिनका आकर्षण अधिकांश लोगों को बना रहता है। सत्ता के मूल में सेवा की भावना है और संपदा के मूल में जीवनयापन की। न सत्ता के बल पर कोई व्यक्ति बड़ा बनता है और न संपदा ही किसी को शिखर पर बिठा सकती है। जो लोग सेवा की पवित्र भावना से सत्ता के गलियारे में पांव रखते हैं और जीवनयापन के साधन के रूप में अर्थ का उपयोग करते हैं, वे सत्ता और संपदा प्राप्त करके भी कुछ अतिरिक्त अनुभव नहीं करते। सहज सादगीमय जीवन जीते हुए वे सत्ता और संपदा के द्वारा हितकारी प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं।

कुछ लोगों की अवधारणा है कि व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व सत्ता और संपदा पर ही निर्भर है। इसलिए वे जैसे-तैसे इन्हें हथियाने का प्रयास करते हैं और ये हस्तगत हो जाएं तो इनका उचित-अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं। ऐसे लोगों में न तो सेवा की भावना होती है और न ही वे उपयोगितावादी दृष्टि से अर्थ का अंकन करते हैं। इनके द्वारा अहंकार बढ़ता है और वे स्वयं को आम आदमी से बहुत बड़ा मानने लगते हैं। यहीं से एक भेद-रेखा बनने लगती है, जो सत्ताधीश और संपत्तिशाली को दूसरे नजरिए से देखने का धरातल तैयार करती है। जिस व्यक्ति के पास सत्ता हो और संपदा हो, फिर भी उन्माद न हो; बहुत कठिन बात है। इन दोनों में से एक पर अधिकार पाने वाला व्यक्ति भी मूढ़ हो सकता है। जहां दोनों का योग हो जाए, वहां मूढ़ता न आए, यह तो संभव ही नहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं, फिर भी सत्ता और संपदा पाने की आकांक्षा का संवरण नहीं होता। जिनकी आकांक्षा पूरी हो जाती है, वे सौभाग्य से ही मूढ़ता से बच पाते हैं। किंतु जिनकी आकांक्षा पूरी नहीं होती, वे एक दूसरे प्रकार के उन्माद का शिकार हो जाते हैं।

किसान आन्दोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेगी

ललित गर्ग

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आन्दोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रश्न है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल न्यायालय के इस महत्वपूर्ण सुझाव को आकार देने की बजाय किसान-आन्दोलन को उग्र करने की मंशा रखते हुए अराजक माहौल ही क्यों बनाना चाहते है? क्यों अव्यवस्था फैलाने चाहते हैं? निश्चित ही शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून-व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है, भारी नुकसान भी हुआ है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार पहले ही दे चुकी है। यह बड़ा सच है कि बात करने से ही बात बनती है। बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। ऐसे आन्दोलन को उग्र करने की विपक्षी दलों की मानसिकता भी संदेहों एवं अविश्वासों से घिरी है। अच्छा हो कि विपक्षी दल एवं नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट में कृषि क्षेत्र के लिये किये गये बड़े ऐलानों पर गौर करें। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम में बदलाव को बरदाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है।

विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों एवं कृषि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध का, अब किसान-आन्दोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में देश का कितना नुकसान होगा, कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि में उत्पादकता, किसानों के हितों एवं कृषि की सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में जो नौ प्राथमिकताएं शामिल है, उनमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से किसानों को निराशा हुई हो लेकिन बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केन्द्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ायेगा एवं उन्नत कृषि को प्रोत्साहन भी देगा।

असल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगें राजनीतिक मुद्दे बन गये हैं, जिनके चलते हो रहा आन्दोलन न केवल किसानों के बल्कि आम जनता के लिये भी परेशानी का सबब है। जबकि सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ा कर 2300 कर दिया है जो स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद थी की सरकार एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्रावधान न होने से काफी निराशा हुई है। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं। लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। विपक्षी दल किसानों के हित में आन्दोलन की बजाय बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े। स्तरीय विरोध हो, किसानों को गुमराह करने एवं उनका मनोबल कमजोर करने के लिये विपक्षी दल उजालों पर कालिख न पोते, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावनाएं है।

मुद्दा: जमानत पर 'सुप्रीम' फैसला

रजनीश कपूर

किसी भी अपराध के संबंध में निर्दोषता की धारणा एक कानूनी सिद्धांत है। जिसके अनुसार किसी भी अपराध के लिए आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। देश की शीर्ष अदालत ने अपने कई आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि 'जमानत देना नियम है और जेल में रखना अपवाद।' परंतु आए दिन यह देखने को मिलता है कि जब भी किसी आरोपी को निचली अदालत से जमानत दी जाती है तो सरकारी एजेंसियां तुरंत उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच कर रोक लगवा लेती हैं। बीते मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने इस चलन पर आपत्ति जताते हुए एक अहम फैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय सिंह ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने धन शोधन के मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश भर के हाई कोर्टों को यह निर्देश दिया कि, 'कोर्ट को स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन किसी की जमानत पर यूं ही रोक नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा करना चाहिए। हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में सोच समझकर फैसला देना चाहिए। सामान्य तौर पर हाईकोर्ट को जमानत के आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए।' उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में गिरफ्तार किया था, लेकिन खुराना को ट्रायल कोर्ट से जून 2023 में ही बेल मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी। जिसे चुनौती देते हुए खुराना सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि, 'एक साल तक एक शख्स बिना किसी कारण के जेल में सड़ रहा है।' केस की पिछली सुनवाई पर ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि खुराना को जमानत मिलते ही वो देश छोड़ कर जा सकता है। यदि वो देश छोड़ कर चला गया तो जमानत के क्या मायने? शीर्ष अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि, 'जमानत पर रोक केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में लगाई जा सकती है। यदि आरोपी पर देशद्रोह, आतंकवाद या एनईए जैसे संगीन मामले दर्ज हों तभी जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए।' गौरतलब है कि देश भर की जेलों में लगभग 6 लाख कैदी बंद हैं। इनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे हैं, जिनका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ, जिन मामलों में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों को तत्परता दिखानी होती है वहां तो रातों-रात गिरफ्तारी भी हो जाती है, परंतु जहां ढील देने का मन होता है या ऊपर से ढील देने के 'निर्देश' होते हैं, वहां विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधियों को देश छोड़ कर भाग जाने का मौका भी दे दिया जाता है। यदि जांच एजेंसियां वास्तव में संगीन अपराधों को गंभीरता से लें तो उन्हें देश में लंबित पड़े सैंकड़ों मामलों में तेजी दिखानी चाहिए। केवल चुनिंदा मामलों में तेजी दिखाने से जांच एजेंसियों पर सवाल तो उठेंगे ही। अब बनी खॅड के मामलों को ही लें तो पिछली लोक सभा में एक सवाल का उत्तर देते हुए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने बताया था कि 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में 'टॉप 50 विल्फुल लोन डिफॉल्टरों' ने बैंकों के साथ 5,40,958 करोड़ धोखाधड़ी की है, परंतु सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स विभाग ने इन मामलों में काफी ढुलमुल रवैया अपनाया। मिसाल के तौर पर लोक सभा में दिए गए इसी उत्तर में देश के 'टॉप 50 विल्फुल लोन डिफॉल्टरों' की सूची में छटे नंबर पर एक नाम 'खॅस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड' का भी है। सूची के अनुसार इनके बैंक खॅड की रकम 3311 करोड़ है। इस कंपनी पर 14 बैंकों के एक समूह के साथ धोखाधड़ी का आरोप है।

गौरतलब है कि बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2020 में उदय देसाई और 13 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई में धोखाधड़ी के मामलों

की एफआईआर लिखवाई थी, परंतु इस मामले की जांच कर रही एजेंसियां किन्हीं कारणों से इस गंभीर मामले में फुर्ती नहीं दिखा रही हैं। 2020 में जब इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी तब यह मामला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 13,000 करोड़ के बैंक खॅड मामले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मामला था, लेकिन इतने संगीन मामले के अपराधी आज तक खुले घूम रहे हैं। वहीं इससे कई छोटे अपराध के मामले में यदि अपराधी जमानत लेता है तो जांच एजेंसियां इसका विरोध करने हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं। ऐसे में देश की शीर्ष अदालत के आदेश के बाद जांच एजेंसियों द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंड का भी पदार्फाश होता है। इसलिए जांच एजेंसियों को संगीन मामलों में फुर्ती दिखानी चाहिए न कि चुनिंदा मामलों में जमानत का विरोध कर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का सामना करना चाहिए।

स्वामी दुर्गम खबर ग्रुप के लिए मुद्रक प्रकाशक ज्योति शर्मा द्वारा मुद्दा हाउस सी ब्लॉक बरात घर के सामने चौरा रघुनाथपुर सेक्टर 22 नोएडा गौतम बुध नगर से मुद्रित एवं ए-28 द्वितीय तल कालिंदी कॉलोनी नई दिल्ली से प्रकाशित संपादक राहुल गुप्ता RNI-No. DELHIN/2008/2623 E MAIL : advtdurgamkhabar@gmail.com, Mob no. +919991351706, 7011031751 किसी भी विवाद की स्थिति में पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदाई

गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल- इस क्रम से फसलों को बोने से भूमि के विभिन्न स्तरों से पोषक तत्वों का समुचित उपयोग हो जाता है। अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल- खेत में लगातार अधिक पानी चाहने वाली फसलें उगाते रहने से मिट्टी जल स्तर ऊपर आ जाएगा। पौधों की जड़ों का विकास प्रभावित होता है एवं अन्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

खेती की एंटीबायोटिक फसलें

फसल चक्र का तरीका

प्रायः फसल चक्र एक से लेकर तीन वर्ष तक के लिए तैयार किया जाता है। अतः फसल चक्र अपनाते समय निम्न सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए।

दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें- दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाये जाते हैं। ये जीवाणु वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे भूमि की उर्वराशक्ति में वृद्धि होती है जो कि आगे बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयोगी होती है।

गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल- इस क्रम से फसलों को बोने से भूमि के विभिन्न स्तरों से पोषक तत्वों का समुचित उपयोग हो जाता है।

अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल- खेत में लगातार अधिक पानी चाहने वाली फसलें उगाते रहने से मिट्टी जल स्तर ऊपर आ जाएगा। पौधों की जड़ों का विकास प्रभावित होता है एवं अन्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल- अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलें लगातार एक ही भूमि में लगाते रहने से भूमि की उर्वराशक्ति का ह्रास शीघ्र हो जाता है एवं खेती की लागत बढ़ती चली जाती है। अतः अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए।

अधिक कर्षण क्रियायें या भूपरिष्करण चाहने वाली फसल के बाद कम क्रियायें चाहने वाली फसल- इस प्रकार के फसल चक्र से मिट्टी की सरंचना ठीक बनी रहती है एवं लागत में भी कमी आती है। इसके अलावा निराई-गुड़ाई में उपयोग किये जाने वाले संसाधनों का दूसरा फसलों में उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

दो तीन वर्ष के फसल चक्र में खेत को एक बार खाली या पड़त छोड़ा जाये- फसल चक्र में भूमि को पड़त छोड़ने से भूमि की उर्वरता में हो रहे लगातार ह्रास से बचा जा सकता है। परती मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पायी जाती है। अतः अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल से पूर्व खेत को एक बार खाली अवश्य छोड़ना चाहिए।

दूर-दूर पंक्तियों में बोई जाने वाली फसल के बाद घनी बोई जाने वाली फसल- वर्षा के दिनों में सघन एवं भूमि को आच्छादित करने वाली फसल लगाने से मिट्टी क्षरण कम होता है जबकि दूर-दूर पंक्तियों में बोई गई फसल से मिट्टी का कटाव अधिक होता है। अतः ऐसी फसलों का हेरफेर होना चाहिए जिससे मिट्टी कटाव एवं उर्वरता ह्रास को रोका जा सके।

दो तीन वर्ष के फसल चक्र में एक बार खरीफ में हरी खाद वाली फसल- हरी खाद के द्वारा भूमि में 40-50 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टर स्थिर होती है। इसके लिए सनई, ढ़ेंचा आदि फसलों का उपयोग किया जा सकता है।

फसल चक्र में साग-सब्जी वाली फसल का समावेश होना चाहिए- किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सफल चक्र में साग-सब्जी वाली फसल का समावेश होना चाहिए।

फसल चक्र में तिलहनी फसल का समावेश होना चाहिए- घर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा फसल चक्र तैयार करना चाहिए जिसमें एक फसल तेल वाली हो।

एक ही प्रकार की कीट व बीमारियों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार एक ही खेत में नहीं बोना चाहिए- एक ही फसल तथा उसी समुदाय की फसलों को एक ही क्षेत्र या एक ही स्थान पर लगातार बोते रहने से कीटों व बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है।

फसल चक्र ऐसा होना चाहिए कि वर्ष भर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता रहे- फसल चक्र निर्धारण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसान के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, सिंचाई इत्यादि का वर्ष भर सदुपयोग होता रहे एवं किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति फसल चक्र में समावेशित फसलों के द्वारा होती रहे।

फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक

भूमि संबंधी कारक: भूमि संबंधी कारकों में भूमि की किस्म, मिट्टी प्रतिक्रिया, जल निकास, मिट्टी की भौतिक दशा आदि आते हैं। ये सभी कारक फसल की उपज पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

सिंचाई के साधन- सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार फसल चक्र अपनाना चाहिए।

किसान की आर्थिक दशा: किसानों की आर्थिक स्थिति का भी फसल चक्र पर प्रभाव पड़ता है। किसान के पास पूंजी एवं संसाधनों की स्थिति को देखते हुए फसल चक्र में ऐसी फसलों का समावेश किया जाना चाहिए जो किसान को अधिकतम लाभ दें।

बाजार की मांग: बाजार की मांग के अनुरूप फसलें ली जानी चाहिए जैसे शहर के नजदीक वाली भूमियों में साग-सब्जी वाली फसलों को प्राथमिकता देना चाहिए।

आवागमन के साधन: आवागमन के समुचित साधन उपलब्ध होने से फसल चक्र में सुविधा के अनुसार फसलों का समावेश करना चाहिए।

श्रमिकों की उपलब्धता: कृषि में श्रमिकों का मुख्य कार्य होता है। यदि श्रमिक आसानी से व पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तो सघन फसल चक्र अपनाया जा सकता है तथा फसल चक्र में नगदी फसलों को समावेशित कर लाभ लिया जा सकता है।

खेती का प्रकार: यदि पशु पालन खेती का मुख्य अवयव है तो ऐसी जगह चारे वाली फसलें की जाये।

किसान की घरेलू आवश्यकताएं: किसान को अपनी घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसल चक्र अपनाना चाहिए।

दलहन की पुख्ता सुरक्षा

फसलों से कम पैदावार मिलने के अनेकों कारण हैं जिनमें फसल की खड़ी अवस्था पर आक्रमण करने वाले हानिकारक कीटों की भूमिका मुख्य है। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि इन कीड़ों से फसल की सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाये।

चने की फली भेधक: पहचान- यह दलहनी फसलों का अत्यंत हानिकारक कीट है जो कि देश के सभी भागों में पाया जाता है तथा वर्षभर सक्रिय रहता है। यह एक बहुभक्षी कीट है। प्रौढ़ शलभ मजबूत एवं हलके भूरे रंग का होता है अगले जोड़ी पंखों पर बिन्दु होते हैं जो कि धारीदार रेखाएं बनाते हैं तथा ऊपर की तरफ काले रंग के धब्बे पाये जाते हैं। पिछले जोड़ी पंख सफेद हल्के रंग के होते हैं। इस कीट की सुंडी के शरीर पर धारियां होती हैं। ये सुंडियां जिस फसल को खाती हैं उसी तरह का रंग ग्रहण कर लेती है।

प्रबंधन

- चने की फसल कटते ही ग्रीष्मकालीन जुताई कर दें ताकि उसमें मौजूद प्यूपा आदि तेज धूप में मर जाये। सुंडियों का पकड़ कर नष्ट करें।
- फसल के आस-पास प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमेन प्रपंच लगाकर प्रौढ़ अवस्था को पकड़ कर नष्ट किया जा सकता है। इन प्रपंचों की संख्या एक हेक्टेयर में 20 हो।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय अवस्था की सुंडियों को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लीयर पाली हायड्रोसिस वायरस (एनपीव्ही) का 350 एलई प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
- कार्बोरिल 10 प्रतिशत अथवा मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल का 20-25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर भुरकाव करें।
- क्विनालफस/ मिथोमिल की 500 मिली/ एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर में दो छिड़काव करें।

कटुआ सुंडी- पहचान- यह चने की सुंडियां नई-नई पत्तियों को खाती है। यह अपना रंग पत्तियों जैसे बना लेती हैं। इस कीट का व्यस्क धूसर रंग का होता है जो कि अधिक उड़ने वाला होता है। इसको चने का कटुआ भी कहते हैं। यह कीट एक विचित्र प्रकार का कीट है। इसका पतंगा बहुत अधिक तेज उड़ने वाला कहा जाता है।

प्रबंधन

- जब खेत खाली हो उस समय खेत की गहरी जुताई करें ताकि जमीन में मौजूद प्यूपा आदि बाहर आकर नष्ट हो जाये।
- छोटे खेतों में/ प्रारंभिक अवस्था में सुंडी का प्रकोप होने पर हाथ से पकड़ कर नष्ट करें।
- खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाकर वयस्क पतंगों को आकर्षित करके नष्ट किया जा सकता है।
- मैलाथियान 5 प्रतिशत अथवा कार्बोरिल 10 प्रतिशत धूल का 20-25 किग्रा प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।

अरहर का प्ररोह मोड कीट

पहचान- इस कीट का पतंगा छोटा, गहरे भूरे रंग का होता है तथा इसकी सुंडी छोटी, हल्के पीले रंग की होती है। सर्वप्रथम सुंडियां पत्तियों की बाह्य त्वचा को खुरचकर खाती है तथा बाद में पत्तियों को मोड़कर अंदर रहकर खाना प्रारंभ कर देती है। सुंडियों मध्यम आकार की चिकनी एवं सफेद पीले रंग की होती है। यह कीट मार्च तथा अप्रैल में खेत में आ जाता है तथा अगस्त माह में अत्यधिक संख्या में पाया जाता है।

प्रबंधन

- मुड़ी हुई पत्तियों को हाथ से तोड़कर नष्ट कर दें।
- फसल पर मिलाथियान 20 ईसी 1.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

अरहर की फल मक्खी

पहचान- प्रौढ़ मक्खी धात्विक हरे रंग की होती है। इसका आकार छोटी, आंखें त्रिभुजाकार, बड़ी तथा हरे रंग की होती है। मादा में जनन शंकु लम्बी होती है। इस कीट के सक्रिय रहने का समय मार्च-अप्रैल होता है।

प्रबंधन-

- प्रारंभिक अवस्था में इस कीट से ग्रसित फलियों को तोड़कर नष्ट कर दें।
- परजीवी मित्र कीट यूडेरस ऐग्रोयाइजी व इलोफिड को संरक्षित करें।
- डायमिथियेट या मिथाइल डिमेटान की 400 मिली/ एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर में दो छिड़काव करें।

खिल उठेगा गेंदा

पावडरी मिलड्यू

इस बीमारी के कारण पत्तियों, शाखाओं एवं पुष्प कलियों पर सफेद फफूंदी का जमाव होता है। जो बाद में भूरे रंग का हो जाता है। जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। और अन्ततः पौधा सूख जाता है। इस बीमारी का प्रकोप फरवरी माह से प्रारंभ होता है।

उपचार

रोग की रोकथाम हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

विषाणु रोग (वायरस)

इस बीमारी के प्रकोप से पत्तियों पर हरे रंग का चितकबरा पड़ जाता है। जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा पुष्प बहुत कम या छोटे आकार के लगते हैं। आमतौर पर इसका प्रसारण संपर्क, हाथो, फसल के अवशेषों , कृषि के यंत्रों तथा कीट द्वारा होता है।

उपचार

रोगोर 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 800 से 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टर खड़ी फसल में छिड़काव करें।

गेंदा फसल में निम्नलिखित प्रमुख कीट लगने की संभावना होती है

माइट (मकड़ी)- गेंदा फसल पर पत्तियों की निचली सतह पर लाल रंग की मकड़ी जाला बनाकर रहते हैं। जो पत्तियों तथा पुष्प कलिकाओं/फूलों से रस चूसते रहते हैं। जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। तथा पुष्प कलिका खिल नहीं पाती पत्तियों पर बना हुआ जाला पौधे की बढ़वार में बाधक होता है।

उपचार- इसकी रोकथाम हेतु रोगोर 0.3 प्रतिशत या मेलाथियान 0.2 प्रतिशत के घोल का छिड़काव पत्तियों के दोनों तरफ करें।

बडबोरर (कलिका वेधक)- इस कीट की इल्लियां पुष्प कलिकाओं में छिद्र करके घुस जाती हैं व अन्दर ही अंदर पुष्प की पंखुड़ियों को खा जाती है। जिससे पुष्प खिल नहीं पाते हैं। एवं पुष्पों का बाजार भाव कम हो जाता है।

उपचार- ग्रसित कलिकाओं / पुष्पों को एकत्र करके नष्ट कर दें। इल्लियों को हाथ से पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। फसल समाप्त होने पर खेत की गहरी जुताई करके प्यूपा को नष्ट कर दें। फसल पर प्रकोप दिखाई देते ही क्विनालफास 0.7 प्रतिशत का छिड़काव आवश्यकतानुसार करें।

हापर (फुदका)- इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों की मुलायम का रस चूसते हैं। फलस्वरुप पत्तियां सिकुड़ जाती है। जो बाद में पीली पड़कर गिर जाती हैं।

उपचार- कीट के नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच खेतों में लगायें चाहिए। फसल में कीट का प्रकोप दिखाई देने पर रोगोर/ डेमोक्रान 0.5 प्रतिशत का घोल का छिड़काव 10-15 दिन के अंतर में 2-3 बार करें।

सरकारी कार्यालयों में कोई भी दलाल या बिचौलिया न रहे सक्रिय इस उद्देश्य से डीएम एवं डीसीपी पुलिस ने एआरटीओ एवं उप रजिस्टार ऑफिस नोएडा का किया औचक निरीक्षण

सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण समय से कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का करें निर्वहन

दुर्गम खबर-गौतमबुद्ध नगर : उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के सभी कार्यालयों में आम जनमानस के कार्यों एवं शिकायतों का बेहतर ढंग से निस्तारण कराने व कार्यालयों में कोई भी दलाल या बिचौलिया सक्रिय न रहे इस उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा नियमित कार्यालयों में पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज जिलाधिकारी एवं डीसीपी पुलिस रामबदन सिंह ने एआरटीओ एवं उप रजिस्ट्रार कार्यालय नोएडा पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कार्यालय में पत्रावलियों को सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव एवं कार्यालय परिसर में बेहतर साफ-सफाई एवं सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी पटल सहायकों से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली और कहा कि जन सामान्य के काम सीधे तौर पर किए जाएं और किसी भी मेडिएटर व्यक्ति की बीच में संलिप्तता न रहे। सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण समय से अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर जनता के कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय अवधि में करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर एआरटीओ एवं उप रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित जनता से भी कार्यों के संबंध में फीडबैक प्राप्त की जोकि संतोषजनक प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि आगे भी इसी प्रकार से जनपद के कार्यालयों में पहुंचकर औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि आम जनमानस को बेहतर सुविधा प्राप्त होती रहे एवं उनके समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय अवधि में गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ डीसीपी पुलिस रामबदन सिंह, एआरटीओ एवं उप रजिस्ट्रार ऑफिस नोएडा के अधिकारीगण तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वाहनों से अवैध वसूली करने वालों पर पुलिस का चाबुक,भष्टाचार पर एक बार फिर चोट

दुर्गम खबर-धीरेन्द्र अवाना

नोएडा। प्रदेश के तेज तर्रार व ईमानदार आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज के कारण चर्चा में है।भष्टाचार को खत्म करने की अपनी मुहीम को चलाते हुए आज वाहनों से अवैध वसूली करने के मामले में तीन पुलिस कर्मियों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया।वहीं इस मामले में कुल 18 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।आपको बता दे कि बलिया में वाहनों से अवैध वसूली करने की लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर एडीजी पियूष मोर्डिया और डीआईजी रेंज आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने सादे कपड़ों में छापेमारी की थी।

दोनों पुलिस अफसरों ने भरौली चौराहे और कोरन्टाडीह पुलिस चौकी पर छापेमारी की।इस दौरान दोनों अफसरों को पुलिस की

कार्यप्रणाली में जबर्दस्त अनियमितता मिली।अफसरों को दलाकों के साथ पुलिसकर्मी ट्रकों से अवैध वसूली करते मिले। बताया जा रहा है कि पूरा मामला बालू तस्करी, शराब तस्करी और पशु तस्करी से जुड़ा है। इस गोरखधंधे में अफसरों ने पुलिसकर्मियों की मिलीभगत पाई है।बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में तीन पुलिसकर्मियों समेत बीस लोगों को पकड़ा गया है।वहीं इस मामले में कुल 18 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है।रेड के बाद नरही थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है।साथ ही नरही क्षेत्र की कोरन्टाडीह पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को भी सस्पेंड कर दिया गया है।अफसरों ने रेड के दौरान अवैध वसूली के 37 हजार 500 रुपये बरामद किए हैं जबकि छापेमारी में 16 बाइक, 50 मोबाइल जब्त किए

गए।बड़ी कार्रवाई के तहत 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छापेमारी मे पकड़े गए 16 दलालों पर भी केस दर्जकर जेल भेजा जा रहा है।इस पूरे मामले की जांच आजमगढ़ एसपी को सौंपी गई है।इससे पहले भी आईपीएस वैभव कृष्ण ने अपने कार्यकाल के दौरान अपराध व अपराधियों को जड़ से खत्म करने का कार्य किया है।

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना में दर्जी के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यार्थियों का किया जाएगा अभिलेखों का सत्यापन

दुर्गम खबर

गौतमबुद्ध नगर : जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निदेशों के क्रम में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गौतम बुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना में दर्जी के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in / msme.up.gov.in पर प्राप्त आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने लिए अभिलेखों का सत्यापन करने हेतु कार्यालय उपायुक्त, उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र सूरजपुर(कलेक्ट्रेट के निकट/पीछे ईकोटेक 2) ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के परिसर में 31 जुलाई 2024 को प्रातः 11:00 बजे से 04:00 बजे अभ्यर्थी प्रस्तुत हो। अभिलेखों का सत्यापन 60 से 100 स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के समय उक्त योजना में प्रशिक्षण के लिए भरे गए ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड सही लिखा हो, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (यदि हो), तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र(यदि हो), आय प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र (यदि हो), विशिष्ट श्रेणी (विधवा/तलाक शुदा/सिंगल मदर/दिव्यांग यदि हो) आदि दस्तावेजों के साथ अभ्यर्थी उपस्थित हो।

एएसपी ने ब्रजघाट का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

दुर्गम खबर-हापुड़। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रांतर्गत ब्रजघाट का पैदल गस्त कर तैयारियों का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए सड़क से लेकर तीर्थ नगरी बृजघाट गंगा घाट का निरीक्षण किया गया, जहां पर हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, गढ़मुक्तेश्वर सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जहां पर पुलिस ने तीर्थ नगरी बृजघाट का पैदल गस्त कर कानून व्यवस्थाओ को परखा, उन्होंने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत तैयारियों का जाजया लिया, वही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस यातायात रूट व्यवस्था के मामले में काफी सख्त नजर आ रही थी, वही गंगा में बैरकटिग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए, वहीं वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे आदि के विषय में भी सख्त निर्देश दिये गए, वही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

तीन मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

हापुड़। थाना कपूरपुर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 05 किलोग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी कार बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 मादक पदार्थ तस्करों को समाना रोड़ बम्बे की पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया है, बताय गया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण टीकम सिंह पुत्र मदनलाल निवासी डोरीनगर गली नं.01 थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़, त्रिलोक चन्द पुत्र होरीलाल निवासी टीचर्स कॉलोनी थाना सासनी जनपद हाथरस, हेमंत पुत्र वेदप्रकाश निवासी पला फाटक डोरीनगर थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़ है। जिनके कब्जे से 05 किलोग्राम अवैद गांजा, तस्करी में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किये गए अभियुक्तगण शातिर किस्म के तस्कर है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डीएम के आदेश को किया नजर अंदाज, राधाकृष्ण इंटर कॉलेज सहित अन्य स्कूल खोले गए, जांच के बाद होगी कार्रवाई : डीआईओएस

हापुड़। कांवड़ यात्रा को लेकर बच्चों की सुरक्षा के लिए डीएम के आदेश पर डीआईओएस द्वारा जिलें के समस्त कालेज व स्कूल के बंद करने के आदेश के बावजूद भी निजामपुर स्थित राधाकृष्ण इंटर कॉलेज सहित अन्य विधालय खोलें गए। इस संबंध में डीआईओएस ने बताया कि जांच के बाद स्कूल संचालकों के विरुद्ध नोटिस भेजकर कार्रवाई की जायेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर बच्चों की सुरक्षा के देखते हुए जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा के आदेश पर डीआईओएस डॉ.विनीता ने जिलें के समस्त समस्त स्कूल, कालेजों को 26 जुलाई से दो अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन निजी स्कूलों कालेजों पर निजी स्कूलों पर डीएम का आदेश बेअसर रहा। आदेश के बाद भी क्षेत्र के निजामपुर स्थित राधाकृष्ण इंटर कॉलेज, कस्तूरबा विद्यालय सहित अन्य कालेज व विद्यालय खुले रहे। डीआईओएस डाक्टर विनीता ने बताया कि प्रशासनिक आदेश को मानना सबका कार्य है। खुलने वाले राधाकृष्ण इंटर कॉलेज सहित अन्य विद्यालयों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कारगिल युद्ध के नायकों और वीर नारियों का सम्मान समारोह हुआ आयोजित

जिलाधिकारी ने सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कारगिल युद्ध के नायकों और वीर नारियों को किया सम्मानित

दुर्गम खबर

गौतमबुद्ध नगर : कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कारगिल युद्ध के नायकों और वीर नारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मान समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ कलेक्ट्रेट में कारगिल नायकों और वीर नारियों के स्वागत के साथ हुआ। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल कपिल कत्याल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने सम्मान समारोह में कारगिल युद्ध के नायकों और वीर नारियों को शॉल एवं मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रत्येक अतिथि से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हुए कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि देश की सुरक्षा में आपके द्वारा दिए गए अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए जिला प्रशासन भी आपके सहयोग के लिए सदैव कटिबद्ध है, यदि आपको कोई भी समस्या आती है, तो जिला प्रशासन के द्वारा आपका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का संचालन सेवानिवृत्त कर्नल शैलेन्द्र सिंह ने किया तथा कारगिल युद्ध के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। बताया गया कि किस प्रकार भारतीय सेना के जांबाजों ने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा तथा पाकिस्तानी सेना को कारगिल क्षेत्र से खदेड़ दिया। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा हॉल यह देश के लिए भारतीय सेना की एक अद्वितीय गौरवपूर्ण जीत थी।

शुभ्रा सिंह ने युद्ध नायकों और वीर नारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार समारोह के बाद सभी प्रतिभागियों के लिए सूक्ष्म जलपान का भी आयोजन किया गया और उन्हें गर्मजोशी से विदा किया गया।

कारगिल विजय दिवस पर बच्चों को सुनाई देश के सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा

दुर्गम खबर-नोएडा। सामाजिक संगठन महिला उन्नति संस्था, जिला गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के सैनिकों के शौर्य और बलिदान की यादगारों को बच्चों में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन साई पब्लिक स्कूल, सदरपुर, सेक्टर 45, नोएडा में किया गया। जिलाध्यक्ष रेनू बाला शर्मा ने बच्चों को कारगिल विजय दिवस के महत्व और हमारे देश के वीर सैनिकों के बलिदानों के बारे में जानकारी दी।उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारे वीर सैनिकों ने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।रेनू बाला ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे हमेशा इस दिवस का सम्मान करें और हमारे सैनिकों के बलिदान को याद रखें। कार्यक्रम में बच्चों ने वीर सैनिकों की याद में नारे भी लगाए।इस कार्यक्रम में अंजनी सिंह, मीना देवी, पार्वती बिष्ट एवं संस्था के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

एजी एनवायरों द्वारा महा अभियान अंतर्गत पौधारोपण

दुर्गम खबर-गौतमबुद्ध नगर : शुक्रवार को भारत युवा परिषद संस्था द्वारा पौधा रोपण महाभियां अंतर्गत नोएडा के सेक्टर 138 में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर आदेश त्यागी ने कहा की हम सभी को रोड के किनारे फुटपाथ पर ज्यादा से ज्यादा फलों फलदार वृक्ष लगाने चाहिए जिससे कि आने-जाने वाले पैदल यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा फल मिल सके और वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं छाया देते हैं इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दे समाज में अच्छे कार्य करने वाले साथियों को सम्मान के रूप में पौधे भी भेंट किए। आदेश कौशिक (अध्यक्ष भारत परिषद) जी ने सभी से आव्हान किया कि अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित व उज्ज्वल बनाने के लिए इस महाभियान से जुड़ें। इसलिए हम सभी को बरसात के टाइम वृक्षारोपण करना चाहिए इस नेक कार्य में दिनेश भाटी (मंडल अध्यक्ष कासना बीजेपी) राजेश सूरी (डे नाइट संस्था) , राहुल राठी ,तेजवीर भाटी,जोनी त्यागी, विक्रम भाटी,आशीष,दीपक भाटी, शहनवाज,पंकज (A.G एनवायरो),लक्की त्यागी, गीता त्यागी (महिला अध्यक्ष जिला गाजियाबाद),संजीव आदि शामिल रहे।

शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत शिक्षा की महत्ता पर एक सेमिनार का किया आयोजन

दुर्गम खबर-बुलंदशहर। कार्यलय जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर के पत्रांक के सन्दर्भ में शुक्रवार को मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर में "शिक्षा सप्ताह" के अन्तर्गत शिक्षा की महत्ता पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत अध्यापकों ने छात्रों को उनके जीवन में शिक्षा महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य मोहम्मद खालिद ने छात्रों को बताया कि यदि आप शिक्षित हैं तो आप अपने समाज और अपने देश की उन्नति और खुशहाली में एक विशेष योगदान दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षित मनुष्य अपने आसपास के लोगो के अंदर अलख जलाकर उनको भी शिक्षित कर लेता है। तथा शिक्षा ही एक ऐसा धन है। जिसका बंटवारा नहीं होता तथा यह बांटने पर और अधिक बढ़ती है।कार्यक्रम में हिन्दी प्रवक्ता आजम खान,भूपेश कुमार,जहीन अहमद , इमरान खान, डा० जमील अहमद आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए।कार्यक्रम का संचालन सय्यद शहजाद हुसैन ने किया।

एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, परिजन में मचा कोहराम

हापुड़। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। जिसके बाद परिजन में कोहराम मचा हुआ है। गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर निवासी काजल पत्नी नरेंद्र महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव उसके ही घर के कमरे में पंखे से फांसी पर लटका हुआ मिला। गांव निवासी एक महिला गुरूवार रात को खाना खाने के बाद सो गई थी। देर रात को जब परिजन की आंख खुली तो उन्होंने कमरे में लाइट जली हुई दिखी। इस दौरान परिजन महिला के कमरे में पहुंचे तो देखा कि महिला का शव पंखे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। महिला के शव को देखकर परिजन की चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। इस दौरान परिजन ने महिला के शव को फंदे से उतारकर चिकित्सक को दिखाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक परिजन ने कोई भी तहरीर नहीं दी है। यदि तहरीर प्राप्त होगी तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

हिंदु जनसंख्या नियंत्रित कर रहे... मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे

-प्रेमानंद महाराज के बयान परमहंस आचार्य ने दी प्रतिक्रिया

अयोध्या। पश्चिम बंगाल में बिगड़ते हालात को देखकर पंचायती अखाड़ा निरंजन के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू बहनें चार बच्चे पैदा करें, जिसमें से 2 हमें सौंप दें। वहीं प्रेमानंद महाराज के बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, 'प्रेमानंद महाराज कथा वाचक हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। सरकार परिवार नियोजन की बात कर रही है। शास्त्रों में संतान उत्पत्ति व्यवस्था की बात कही गई है। प्रेमानंद महाराज को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, 'हिंदुस्तान में कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम हुई है और कई जगह अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जहां हिंदू कम हो रहे हैं, वहां सरेआम गाय की हत्या हो रही है। निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं। हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचने के लिए प्रेमानंद महाराज ने ये बात कही है। हिंदू अपने आप जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं से 10 गुना ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वहां हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है।

सीमा हैदर की सगी बहन का आरोप... अय्याशी और पैसा चाहिए

नई दिल्ली । खुद को सीमा हैदर की बहन बताते हुए एक बुर्कानशी महिला ने पाकिस्तानी भाभी को खूब खरी-खोटी सुनाई है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के चैनल पर महिला ने खुद को सीमा हैदर की सगी बहन बताकर भारत सरकार से अपील की कि बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। 10 मिनट के वीडियो में महिला फूट-फूटकर रोई और सीमा को अय्याश और डायन कहकर कोसती रही। सीमा हैदर की कथित बहन ने कहा, मैं भारत सरकार से कहूंगी कि आप उसको (सीमा) को रखो। लेकिन बच्चों को वापस भेज दो। खुदा के लिए हमारी मदद करो। वह डायन बच्चों को मार देगी अपनी अय्याशी के लिए। उस कुछ नहीं चाहिए, उसको अय्याशी चाहिए, पैसा चाहिए, मेकअप चाहिए उसको वीडियो बनानी है, सारी दुनिया को दिखानी है। उसे बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। किस तरह की कपड़े पहनाती है, लोग उन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उनका वीडियो बनाकर डालते हैं। सीमा की बहन ने रोते हुए कहा, हम पर रहम करो। हमारे बच्चे को पाकिस्तान डिपोर्ट करो। हमें नहीं चाहिए। उसे रखो अपने पास, उसे नचवाओ, उससे पैसे कमबाओ, उसका जो करवाना है करवाओ, लेकिन चार बच्चों की जिंदगी तबाह मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस तरह की मां हो। किस तरह बच्चों के कपड़े पहनाती हो, तुम्हारे बच्चों के लोगों ने प्राइवेट पार्ट के वीडियो बनाकर पैसे कमाए हैं। खुदा के लिए उन बच्चों को छोड़ दो। उनका क्या कसूर है, यही ना कि तुम उनकी मां हो।

गुप्त दान देने वालों पर शिकंजा नहीं कस सकता है, आयकर विभाग- हाईकोर्ट

मुंबई । मुंबई हाईकोर्ट ने शिर्डी के सांई बाबा ट्रस्ट को मिलने वाले गुप्त दान पर दायर आयकर विभाग की याचिका पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है, आयकर विभाग मंदिरों को गुप्त दान देने पर भक्तों की भावना को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति सोमशेखर की खंडपीठ ने कहा सांई बाबा भगवान दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं। भक्त उनकी पूजा करते हैं। जो भी दान भक्त करते हैं। वह उनकी आस्था का प्रतीक है। साईं बाबा ट्रस्ट एक धार्मिक संस्थान है। इसे आयकर से छूट प्राप्त है। आयकर ट्रिब्यूनल का मानना है, सांई बाबा ट्रस्ट धर्माथ है, धार्मिक ट्रस्ट नहीं है। आयकर विभाग का कहना था। ट्रस्ट की आय 400 करोड रुपए से ज्यादा की है। धार्मिक कार्यों पर ट्रस्ट ने मात्र 2.30 करोड रुपए ही खर्च किए हैं। आयकर विभाग का कहना था, धार्मिक कार्यों के लिए यह राशि खर्च नहीं की जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट की खंड पीठ ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।

कंगना रनौत ने लोकसभा में कांग्रेस को खूब सुनाया, बोलीं- पिछले 10 साल में जितना विकास हुआ है, 60 साल में नहीं हुआ

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 26 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश इतना फला-फूला, जो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ था। उन्होंने भ्रष्ट नीतियों को लागू करने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की। कंगना ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि दस साल पहले देश में अर्थव्यवस्था चरमराती और लडखड़ाती हालत में थी, लेकिन पिछले दस साल में यह विश्व में 11वें स्थान से पांचवें नंबर पर आई है और तीसरे स्थान की ओर बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से निर्वाचित भाजपा सांसद ने कहा कि उनके राज्य में पिछले साल आई बाढ़ में व्यापक जनधन की हानि हुई और राज्य सरकार की ''लापरवाही की वजह से अब भी हिमाचल त्रासदी की हानि से बाहर नहीं आ पा रहा।'' उन्होंने बजट में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए विशेष पैकेज की घोषणा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ''पिछले दस साल में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में जितना विकास का काम किया है, उतना 60 साल में भी नहीं हुआ।'' कंगना ने कहा कि राज्य को अटल सुरंग जैसी वैश्विक अवसंरचना वाली परियोजनाएं मिली हैं, 11 हजार करोड़ रुपये की जलविद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गईहैं। उन्होंने मंडी में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की मांग सरकार से की। उन्होंने कहा, ''इस बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है और तब भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगा।'' उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को सशक्त बनाने वाला है। कंगना ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी।

अग्निपथ योजना पर खुलेआम झूठ बोल रहे पीएम मोदी : खड़गे

-पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के बयान का ज़िक

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कारगिल विजय दिवस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आलोचना पीएम मोदी द्वारा द्रास में एक संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्ष पर निशाना साधकर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे अवसरों पर भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कि पीएम मोदी का दावा कि उनकी सरकार ने सेना के आदेश पर अग्निपथ योजना लागू सरासर झूठ और हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अक्षम्य अपमान है। खरगे ने कहा कि मोदी जी, आप ही हैं जो झूठ फैला रहे हैं! पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 75 प्रमतिशत भर्तियों को स्थायित्व के लिए लिया जाना था और 25 प्रतिशत लोगों को 4 साल बाद जाने दिया जाना था। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उलटा कर योजना को तीनों सशस्त्र बलों के लिए जबरन लागू कर दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक में, इस मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक दिया है, कहा है कि अग्निपथ योजना सेना और नौसेना और वायु सेना के लिए चौंकाने वाली थी।

मुंबई में भारी बारिश... पुलिस की लोगों को सलाह घर पर ही रहे

मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया

मुंबई (एजेंसी)। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद पुलिस ने मुंबई निवासियों को शनिवार सुबह 8:30 बजे तक घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। यह सलाह भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद है। पिछले 24 घंटों में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक मुंबई शहर में 44 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 90 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 89 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का आकलन कर रायगढ़ कलेक्टर को बाढ़ प्रभावित निवासियों की सहायता करने का निर्देश दिया। भूस्खलन के कारण रायगढ़-पुणे मार्ग पर तम्हिनी घाट पर यातायात रोक दिया गया।

पुणे में सड़कों पर और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खडकवासला बांध और जलग्रहण क्षेत्र में काफी बारिश हो रही है। जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त अलर्ट पर हैं, सीएम शिंदे ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य समकक्ष की टीमों को तैनात किया गया है, और सेना की एयरलिफ्टिंग टीमें स्टैंडबाय पर हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा संदेश

मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, आईएमडी ने कल सुबह 8:30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। सभी मुंबईवासियों से अनुरोध है कि जब तक जरूरी न हो, घर के अंदर ही रहें। कृपया सुरक्षित रहें। आपात स्थिति के लिए 100, 112 डायल करें।

रनवे परिचालन को पहले सुबह 8:32 बजे से सुबह 8:43 बजे तक 11 मिनट के लिए रोका गया, और फिर सुबह 10:36 बजे से 10:55 बजे तक 19 मिनट के लिए रोका गया क्योंकि दृश्यता 300 मीटर तक गिर गई और रनवे विजुअल रेंज (आरवीआर) गिर गई।

यात्री मार्गदर्शन

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरलाइन वेबसाइटों और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें और मुंबई में चल रही भारी बारिश और यातायात की भीड़ के बीच हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाएं।

पुतिन-मोदी मुलाकात से भन्नाया चीन... अब चौधरी बनने में जुटा

नई दिल्ली। भारत और रूस की दोस्ती की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या कोई बड़ा मसला दोनों ने शुरू से एक-दूसरे का साथ दिया है। लेकिन भारत और रूस की यारी से चीन परेशान हो रहा है। चीन दोस्ती में दरार लाने की हरसंभव कोशिश करता रहता है। मगर यह दोस्ती अटूट है। खुद अमेरिका मानता है कि रूस-यूक्रेन जंग में भारत ही शांति दूत का काम कर सकता है। इस हकीकत से अनजान होकर चीन रूस-यूक्रेन जंग में चौधरी बनना चाहता है। दरअसल, जब से जंग भड़की है, चीन रूस पर डोरे डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। ड्रैगन ने पुतिन को अलग-अलग तरीकों से बीते कुछ समय से लुभाने का प्रयास किया है। मगर पीएम मोदी के मॉस्को दौरे ने चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चीन अब पीएम मोदी की पुतिन संग मुलाकात से भन्ना गया है। आनन-फानन में चीन रूस-यूक्रेन जंग और हमास-इजरायल जंग खत्म करवाने की झूठी कवायद में जुट गया है। इसके लिए चीन ने हमास और फतह के बीच सुलह करा दी है। ये दोनों कट्टर दुश्मन रहे हैं। चीन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री को बीजिंग में बुला लिया। वह यूक्रेन को भरोसा दिला रहा है कि वह शांति दूत बनकर जंग खत्म करा देगा। यूक्रेनी विदेश मंत्री का बीजिंग आया इसलिए भी खास है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद पहली बार चीन ने किसी यूक्रेनी नेता की बीजिंग में मेजबानी की है। दरअसल चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में वह अब चीजें तय कर सकता है। चीन यूक्रेनी विदेश मंत्री संग मुलाकात के जरिए खुद को एक तटस्थ और शांति दूत के तौर पर पेश करना चाहता है जबकि हकीकत यह है कि चीन जंग को और भड़काता रहा है।

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का समर्थन करना चन्नी को पड़ा भारी, कांग्रेस घिरी

-बीजेपी बोली-कांग्रेस अलगाववादियों और आतंकवादियों की वकालत क्यों करती है?

नई दिल्ली (एजेंसी)। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में कांग्रेस के लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही है। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने चन्नी के बयान से कन्नी काट ली है। कांग्रेस ने साफ कहा कि चन्नी के विचार पार्टी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने और निजी हैं, और किसी भी तरह से कांग्रेस की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

चन्नी के बयान के बाद बीजेपी, कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चन्नी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी की दादी और दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे खालिस्तान का विचार था। उन्होंने कहा कि भारत के टुकड़े-टुकड़े चाहने वाले अलगाववादी के लिए बल्लेबाजी? राहुलजी को जवाब देना चाहिए कि खालिस्तान के जिस विचार के कारण पीएम इंदिराजी की हत्या हुई, उसकी सराहना की जा रही है। कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों की वकालत क्यों करती है?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद चन्नी की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, उसे आज चन्नी का खुला समर्थन मिल गया है, इसका मतलब है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। यह भारत की अखंडता पर हमला है...कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्होंने बजट पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने आपातकाल पर बात की। मुझे लगता है चन्नी को नहीं पता। उन्हें पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारे संविधान के साथ क्या किया था। चन्नी को इतिहास पढ़ना चाहिए और आप पंजाब के पूर्व सीएम हैं। आपको 1984 के दंगों के पीड़ितों की विधवाओं से मिलना चाहिए।

मुझे मत सिखाओ, बल्कि मेरे से सीख लो, बांग्लादेशियों को शरण देने वाले मुद्दे पर विदेश मंत्रालय को ममता की नसीहत

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के शरणार्थियों को आश्रय देने की उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) पर पलटवार किया। बनर्जी ने कहा कि मैं संघीय ढांचे को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं सात बार सांसद रही, मैं दो बार केंद्रीय मंत्री रही। मैं विदेश मंत्रालय की नीति को किसी और से बेहतर जानती हूं। उन्हें मुझे सबक नहीं सिखाना चाहिए। उन्हें इससे सीखना चाहिए। नौकरी में आरक्षण के विरोध को लेकर बांग्लादेश में हुई हिंसक झड़पों के बाद ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बात की थी। उनकी टिप्पणी कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आई, जहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की 'शहीद दिवस' रैली में कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बनर्जी की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से कहा कि उनकी टिप्पणियां भ्रम पैदा कर सकती हैं और जनता को गुमराह कर सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसे ममता बनर्जी की टिप्पणी पर ढाका से एक लिखित आपत्ति मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि विदेशी संबंधों से जुड़े मामले केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।

जयसवाल ने कहा कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची - सूची एक - संघ सूची - आइटम 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है।

कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी विशेष कोर्ट में हुए हाजिर, दर्ज कराया अपना बयान

सुलतानपुर । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में राहुल गांधी ने अपने वकील काशी प्रसाद शुक्ल व परिवादी के वकील संतोष पांडेय की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने परिवादी के साक्ष्य के लिए 12 अगस्त की तारीख नियत की है। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया बंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत पहले ही हो चुकी है। कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट से बाहर आते ही राहुल गांधी जिन्दाबाद के जमकर नारे लगे।

बजट में नहीं मिली राहत, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्याज बनेगी मुद्दा

मुंबई, (एजेंसी)। एनडीए सरकार को हाल के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के प्याज बेल्ट में झटका लगा है। पार्टी को छह सीटों में से केवल एक पर जीत हासिल हुई है। मुख्य रूप से फसल निर्यात पर प्रतिबंध के चलते व्यापारियों के रूप में आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। किसानों में बजट द्वारा इस पर प्रतिबंध न हटाए जाने पर निराशा है। प्याज के मुफ्त निर्यात पर लंबे समय तक प्रतिबंध एनडीए की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, नासिक में एक बीजेपी नेता ने निराशा जताते हुए कहा कि हमारे नेता इसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को समझाने में सक्षम नहीं थे।

डिंडोरी, नासिक, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर और धुले लोकसभा सीटें राज्य की प्याज बेल्ट वाली हैं, जो देश के प्याज उत्पादन का करीब 34फीसदी हिस्सा है। राज्य की 40फीसदी से ज्यादा प्याज की खेती नासिक में ही होती है। औरंगाबाद को छोड़कर, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संदीपन भुमरे ने जीत हासिल की, बाकी सभी सीटें एनडीए हार गईं है। अहमदनगर और बीड में, एनसीपी (सपा) के नीलेश लंके और बजरंग सोनावणे जैसे अपेक्षाकृत नए लोगों ने सुजय विखे-पाटिल और पंकजा मुंडे जैसे बीजेपी के दिग्गजों को हार का मजा चखाया है।

नासिक जिले के बलगन तालुका से शिवसेना नेता (शिंदे गुट) ने कहा कि विपक्ष लगातार प्याज की कीमतों का मुद्दा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने नेताओं से निर्यात का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाने को कहा था। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बजट में इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है, इसका उल्टा असर पड़ सकता है। निर्यात प्रतिबंध के कारण पिछले साल ज्यादातर समय प्याज की कीमतें कम रहीं। डिंडोरी लोकसभा सीट के एक किसान ने कहा कि सरकार बजट में प्रतिबंध हटा देगी, लेकिन लगता है कि केंद्र ने इससे सबक नहीं सीखा है। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बना रहेगा। हम लोगों में से ज्यादातर सरकार के इस कदम से आहत हैं।

केजरीवाल की सेहत को लेकर इंडिया गठबंधन का 30 को दिल्ली में प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक रैली आयोजित कर रहा है, जिसमें तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरती सेहत का मुद्दा उठाया जाएगा। आप नेता बीजेपी पर जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया है कि तीन जून से सात जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 26 बार नीचे आया।

आप नेताओं ने कहा कि केजरीवाल की गिरती सेहत का मुद्दा उठाने के लिए इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक बड़ी रैली करेगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर सीएम केजरीवाल की जान से खेलने का आरोप लगाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी से रैली के बारे में कहा कि बीजेपी दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। वह दिल्ली के लोगों के काम रोक रही है। वह दिल्ली के लोगों के पैसा रोक रही है। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है।

आतिशी ने यह भी दावा किया कि जब बीजेपी को पता चला कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है तो उन्होंने उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करवाया। आतिशी ने दावा किया कि उन्हें पता है कि केजरीवाल को पिछले 30 सालों से डायबिटीज है। हिरासत में उनका वजन 8.5 किलो कम हो गया है। ग्लूकोमीटर पूरे दिन उनके शुगर लेवल पर नजर रखता है। इस डिवाइस का डेटा एलजी और केंद्र के साथ साझा किया जाता है। उन्हें पता है कि केजरीवाल का शुगर लेवल कुल 34 बार गिरा है। बीजेपी चाहती है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए।

सभी ब्लॉक पार्टियां केजरीवाल की हिरासत और उनके स्वास्थ्य पर मौजूदा खतरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। पिछले हफ्ते, वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को केजरीवाल

की स्वास्थ्य स्थिति को रेखांकित करते हुए लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ जेल अधीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट से पता चला है कि सीएम जानबूझकर अनुशंसित कैलोरी से कम कैलोरी ले रहे हैं। एलजी ने तत्काल कार्रवाई और केजरीवाल के रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की।

अग्निपथ योजना पर खुलेआम झूठ बोल रहे पीएम मोदी : खड़गे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कारगिल विजय दिवस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आलोचना पीएम मोदी द्वारा द्रास में एक संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्ष पर निशाना साधकर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे अवसरों पर भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी का दावा कि उनकी सरकार ने सेना के आदेश पर अग्निपथ योजना लागू सरासर झूठ और हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अक्षम्य अपमान है। खरगे ने कहा कि मोदी जी, आप ही हैं जो झूठ फैला रहे हैं! पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 75 प्रमतिशत भर्तियों को स्थायित्व के लिए लिया जाना था और 25 प्रतिशत लोगों को 4 साल बाद जाने दिया जाना था। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उलटा कर योजना को तीनों सशस्त्र बलों के लिए जबरन लागू कर दिया।

नीट पेपर लीक मामला: अधजले पेपरों ने सीबीआई को आरोपियों तक पहुंचाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। । नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आधे जले हुए पेपर ने सीबीआई को एक अहम सुराग मिला और उसने पेपर लीक मामले को सुलझाने में मदद की। नीट पेपर लीक मामले में अपने आधिकारिक बयान में सीबीआई ने अपराध के बारे में खुलासा किया। सीबीआई के मुताबिक नीट यूजी 2024 पेपर पांच मई, 2024 को झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल से अवैध रूप से प्राप्त किया गया था।

सीबीआई ने कहा कि पंकज कुमार जिसे आदित्य और साहिल के नाम से भी जाना जाता है, पेपर लीक के पीछे के मास्टरमाइंड में से है, साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक सहयोगी परीक्षा के पेपर तक अनाधिकृत पहुंच में शामिल थे।

आधे जले हुए पेपरों के बरामद टुकड़ों ने सीबीआई को नीट परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद की, जहां से इसे लीक किया गया था। पांच मई की सुबह नीट पेपर से भरे ट्रंक स्कूल लाए गए और उन्हें नियंत्रण कक्ष में रख दिया गया। सीबीआई ने कहा कि ट्रंक पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड को कमरे में जाने दिया।

गिरोह ने पेपर से भरे ट्रंक को खोलने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया और बिना इजाजत उसमें से सामग्री निकाल ली। पेपर तक पहुंचने के बाद, इसे हजारीबाग में एमबीबीएस छात्रों द्वारा हल कराया गया। हल किए गए पेपर को फिर चुनिंदा छात्रों को पहुंचा दिया गया, जिन्होंने उत्तरों के लिए रकम भी दी। सीबीआई ने ऑपरेशन में शामिल अधिकांश सॉल्वरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों को ऐसे व्यक्तियों के एक नेटवर्क का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने उम्मीदवारों के आवास और उनके परिवहन का प्रबंध किया था।

वर्तमान में उन सभी छात्रों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें लीक हुए पेपर मिले थे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। इस साल 23 जून से चल रही सीबीआई जांच में अब तक 36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें बिहार पुलिस द्वारा पकड़े गए 15 लोग शामिल हैं।

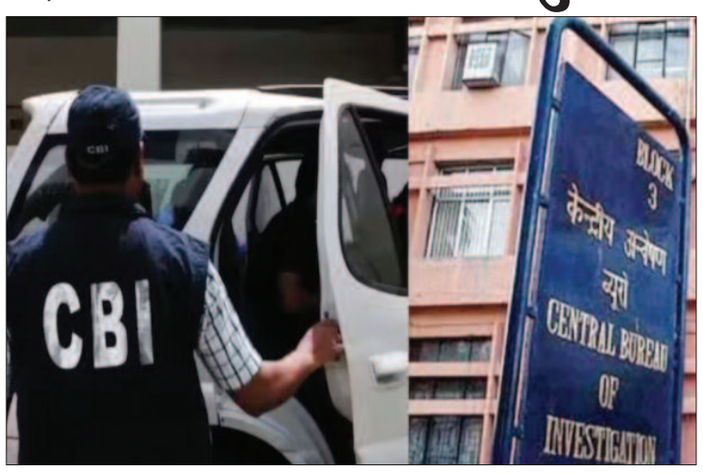

दुनिया की 73.3 करोड़ आबादी खाली पेट सोने को मजबूर, पिछले 5 वर्षों में 233 करोड लोग कुपोषण के शिकार

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2024 की रिपोर्ट में विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कॉविड-19 के पहले जो स्थिति थी। उससे भयावह स्थिति में 2024 मे हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 11 इंसान मे 1 इंसान खाली पेट सोने के लिए मजबूर हो गया है। दुनिया के देशों में 73.3 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी अल्प पोषण के शिकार है। 2019 में ऐसे लोगों की संख्या मात्र 15.2 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट में अफ्रीका के देशों की स्थिति इसमें सबसे ज्यादा खराब है। यहां हर पांचवा व्यक्ति भुखमरी का शिकार है। दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों द्वारा जिस तरह से खाद्य पदार्थों विक्रय किये जा रहे हैं। उनके 90 फ़ीसदी उत्पाद कुपोषण को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। पेकफूड के उत्पाद कुपोषण बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 233 करोड़ आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया के 86.4 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से गुजर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सारी दुनिया के देश कुपोषण के मामले में 2008-09 की तुलना में काफ़ी नीचे चले गए हैं। पिछले 15 वर्षों में हालत में सुधार होने थे। उससे भी खराब स्थिति में दुनिया के देश पहुंच गए हैं। दुनिया के लिए यह चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है।

उत्तरी जापान में बाढ़ व भूस्खलन से सैकड़ों लोग बेघर, शरण लेने को मजबूर

टोक्यो। देश ही नहीं इस बार बारिश ने कई दशों में तबाही मचा रखी है। उत्तरी जापान में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से आवागमन बाधित हो गया है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जापान मौसम विभाग ने यामागाटा और अकिता प्रांत के कई शहरों के लिए चेतावनी जारी की है। इन शहरों में अब तक गर्म हवाएं चलने के कारण उमस से लोग परेशान थे। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने प्रभावित इलाकों के लोगों से मौसम संबंधी जानकारियों पर लगातार नजर बनाए रखने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। अकिता प्रांत के युजावा शहर में एक व्यक्ति सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युजावा में बचाव कर्मियों ने नाव की मदद से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से 11 प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला है। यामागाटा प्रांत में सबसे त्यादा प्रभावित युजा और सकाटा कस्बों में एक घंटे में चार इंच से ज्यादा बारिश हुई। क्षेत्र के हजारों लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई। हालांकि, शरण लेने वाले लोगों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। पूर्वी जापान यामागाटा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से निलंबित कर दी गईं हैं। यहां भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

साइबर हमले के लिए उत्तर कोरियाई का हैकर जिम्मेदार!

वाशिंगटन। संघीय अभियोजकों ने घोषणा की कि उत्तर कोरिया की सैन्य खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले एक व्यक्ति पर अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की साइबर सेल में सेंध लगाने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि कंसास में एक 'ग्रैंड जूरी' ने रिम जोंग ह्योक को हिरासत में लिया है जिस पर फिरौती के पैसे को वैध बनाने और उस धन का इस्तेमाल दुनिया भर में रक्षा, प्रौद्योगिकी और सरकारी संस्थाओं पर अतिरिक्त साइबर हमलों के लिए करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर हैकिंग के कारण मरीजों के उपचार में बाधा आई।

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान की पार्टी के 39 सदस्यों को माना सांसद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने आरक्षित सीटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान की पार्टी के 39 निर्वाचित उम्मीदवारों को सांसद के तौर पर अधिसूचित किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीट हासिल करने के योग्य घोषित किया था। पीटीआई को संसदीय दल घोषित करने के बाद बड़ी राहत मिली थी। अधिकतर जजों ने पाया कि चुनाव आयोग ने उल्लेखित नेशनल असेंबली के पीटीआई के 80 में से 39 सदस्य पार्टी से संबद्ध हैं। शेष 41 सदस्यों को 15 दिन में चुनाव आयोग को बताना होगा कि उन्होंने आठ फरवरी का आम चुनाव पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। आयोग ने पिछले सप्ताह कोर्ट के आदेश के पालन का फैसला किया था।

हर साल डूबने से करीब 236,000 लोगों की मौत... डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने बताया कि दुनिया भर में हर साल डूबने से करीब 236,000 लोगों की मौत होती है। यह आंकड़ा प्रतिदिन 350 या प्रति घंटे 26 है। हर साल 25 जुलाई का दिन वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डूबने से 70,034 लोगों की जान चली गई, इससे यह दुनिया भर में डूबने से होने वाली मौतों में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। उन्होंने कहा, डूबना एक अचानक और खामोश मौत है। अधिकांश घटनाएं निगरानी की कमी, खतरनाक जल निकायों के संपर्क में आने, अपर्याप्त जागरूकता और गरीबी के कारण घरों के पास होती हैं। वाजेद ने कहा कि इसके लिए कई निवारक उपाय मौजूद हैं जो इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वाजेद ने कहा, डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम में हम सभी की भूमिका आवश्यक है, चाहे जागरूकता बढ़ानी हो, प्रभावी समाधानों के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना हो, स्थानीय या राष्ट्रीय सरकारों के साथ रोकथाम योजनाओं और नीतियों पर सहयोग करना हो, संबंधित संगठनों के साथ स्वयं सेवा करनी हो या पानी के आसपास व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, हममें से हर कोई इसमें बदलाव ला सकता है।

कनाडा के टूरिस्ट शहर जेसपर में जंगल की आग पहुंच गयी जिसके बाद दमकलकर्मयों को लोगों को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा।

हैरिस की नेतन्याहू को दो टूक... गाजा में मासूमों की हत्या पर चुप नहीं रहूंगी

वॉशिंगटन। अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कमला हैरिस से मुलाकात की। मुलाकात में कमला हैरिस ने हमास के द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों के मुक्त करवाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नेतन्याहू को दो टूक कहा कि गाजा में मासूमों की हत्या पर वे चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि तत्काल बातचीत के जरिए युद्धविराम की जरूरत है।

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हैरिस ने कहा कि गाजा में युद्धविराम जरूरी है। यहां लाखों की संख्या में मासूमों की जान पर बनी है और वे भुखमरी के शिकार हैं। हैरिस ने कहा कि वह गाजा के लोगों की दिक्कतों को लेकर चुप नहीं रहेंगी। हैरिस ने कहा कि इजरायल को अपने बचाव का अधिकार है लेकिन बीते 9 महीने में जो कुछ भी हुआ वह बेहद खतरनाक और विनाशकारी है। बता दें कि गाजा युद्ध से डेमोक्रेटिक पार्टी में भी इस मामले को लेकर दो धड़े बन गए हैं। हालांकि कमला का बयान पार्टी में बैलेंस बनाने वाला लगता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने कहा कि सभी लोग आतंकवाद, हिंसा, इस्लामोफोबिया और हेट की आलोचना करते हैं। हालांकि मानवता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गाजा में 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने जो बाइडेन से भी मुलाकात की थी।

भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' का आधार है आसियान, लाओस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर खुलकर बोले जयशंकर

वाशिंगटन (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत के लिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) उसकी एक्ट ईस्ट नीति और उसके इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण की आधारशिला है। आसियान-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए, आसियान उसकी एक्ट ईस्ट नीति और उसके बाद बने इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण की आधारशिला है। हमारे लिए आसियान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों से लोगों के बीच संबंध भी ऐसे ही हैं जिनका हम लगातार विस्तार करना चाह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत आसियान को कितनी प्राथमिकता देता है, यह पिछले साल हमारे अपने जी-20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर प्रधान मंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा से स्पष्ट था। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने 12-सूत्रीय योजना की घोषणा की थी जिस पर काफी हद तक काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जानना उत्साहजनक है कि भारत-आसियान साझेदारी हर गुजरते दिन के साथ और अधिक आयाम हासिल कर रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा जयशंकर कि लाओस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि यह वर्ष भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक का प्रतीक है, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में

की थी।

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक राजनयिक पहल है। भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना करता है, जो नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर बना हो। आसियान के 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। इससे पहले शुक्रवार को जयशंकर ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष विंस्टन पीटर्स से मुलाकात की और शिक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशांत द्वीप समूह और क्रिकेट पर चर्चा की।

अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की कब होगी वापसी? नासा ने दिया स्पेस स्टेशन से चिपके बोइंग स्टारलाइनर का अपडेट

वाशिंगटन (एजेंसी)। पिछले डेढ़ महीने से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर नासा ने नया अपडेट दिया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर जुलाई में पृथ्वी पर नहीं लौटेंगे। नासा ने कहा कि उनके बोइंग कैप्सूल में आई दिक्कतों को इंजीनियर के दूर करने तक वे आईएसएस पर ही रहेंगी। स्टारलाइनर टीम अब अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए डेटा की समीक्षा कर रही है। न्यू मैक्सिको में नासा की व्हाइट सैंड्स टेस्ट सुविधा में आरसीएस थ्रस्टर परीक्षण ने मूल कारण मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की और नाममात्र अनडॉक और लैंडिंग के लिए उड़ान तर्क को अंतिम रूप देने में मदद की।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्टारलाइनर कार्यक्रम प्रबंधक और उपाध्यक्ष मार्क नैप्पी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास चालक दल को वापस लाने के लिए एक अच्छा वाहन है। टीम ने इस सप्ताह के अंत में 28 आरसीएस थ्रस्टर्स में से 27 को गर्म करने की योजना बनाई है, जबकि अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में सुरक्षित रूप से डॉक किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य थ्रस्टर्स के प्रदर्शन को सत्यापित करना और अतिरिक्त हीलियम रिसाव डेटा इकट्ठा करना है, जो 6 जून को अंतरिक्ष यान के आगमन के बाद से स्थिर बना हुआ है।

रवानगी के एक दिन बाद छह जून को 'कैप्सूल' के अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचने पर पांच थ्रस्टर में गड़बड़ी आ गई। तब से चार को फिर से चालू किया जा चुका है। स्पेस शटल के सेवा से हटने के बाद, नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन पर आवाजाही के लिए निजी कंपनियों को काम पर रखा है, जिसके लिए बोइंग और स्पेसएक्स को अरबों डॉलर का भुगतान किया गया है। यह बोइंग की पहली परीक्षण उड़ान थी जिसमें चालक दल सवार था। स्पेसएक्स 2020 से मानव को अंतरिक्ष में ले जा रहा है।

कमला हैरिस अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप को हरा देंगी, ओबामा को नहीं है यकीन

-बराक का सपोर्ट हैरिस की जीत-हार में निभा सकता है बड़ा रोल

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है और सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए जी जान से जुटी हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने खुद इस चुनाव से पीछे हटते हुए कमला हैरिस को सपोर्ट किया है और आज फिर उनकी तारीफ करते हुए उन्हें वोट देने की अपील की।

बाइडन के इस ऐलान के बाद ज्यादातर डेमोक्रेट्स नेता तुरंत ही हैरिस के पीछे खड़े हो गए। हालांकि इसमें सबसे खटकने वाली बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब तक उन्हें लेकर कोई बयान नहीं दिया है। एक रिपोर्ट में बाइडन परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया गया कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को यकीन नहीं है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाएंगी। इसलिए उन्होंने इस चुनाव में हैरिस का समर्थन करने से परहेज किया है। वैसे डेमोक्रेट्स समर्थकों में बराक ओबामा की आज भी काफी अपील मानी जाती है। ऐसे में उनका सपोर्ट हैरिस की जीत-हार में बड़ा रोल निभा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओबामा परेशान हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कमला हैरिस जीत नहीं सकती हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि वह अयोग्य हैं। वह आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका था, जबकि राष्ट्रपति चुनाव से इतने दिन पहले टीवी डीबेट रखा गया। आमतौर पर ऐसे डीबेट चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में होते हैं। वहीं बाइडन समर्थन का दावा है कि मौजूदा राष्ट्रपति को रेस से बाहर करने के लिए जानबूझकर यह किया गया था। बाइडन परिवार के करीबी सूत्र ने आशंका जताई कि ट्रंप के खिलाफ टीवी डीबेट में हैरिस भी नहीं टिक पाएंगी। उन्होंने शक जताया कि इजरायल, फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर वह गलत बयान दे सकती हैं। अपनी बात रखते हुए ही वो कोई न कोई गलती कर बैठेंगी।

म्यांमार के एनएसए से मिले अजीत डोभाल, द्विपक्षीय बैठक में हुई अहम बातचीत

(एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और उनके म्यांमार समकक्ष एडमिरल मो आंग के बीच एक बैठक में म्यांमार में हिंसा और अस्थिरता के परिणामों के बारे में भारत की चिंताओं पर चर्चा हुई। डोभाल बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए म्यांमार में हैं। यह 2021 में जुंटा द्वारा तख्तापलट के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारी की म्यांमार की पहली यात्राओं में से एक है। पिछले साल अक्टूबर में कई सशस्त्र समूहों द्वारा समन्वित आक्रमण शुरू करने के बाद से जुंटा को प्रतिरोध बलों और लोगों की रक्षा बलों के हाथों अपमानजनक सैन्य हार का सामना करना पड़ा है।

आक्रामक को जुंटा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 1 फरवरी, 2021 को तख्तापलट में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से म्यांमार में व्यापक हिंसा देखी जा रही है। चूंकि प्रतिरोध बलों ने सैन्य पदों पर कब्जा कर लिया है और प्रमुख व्यापारिक पदों पर कब्जा कर लिया है। भारत, बांग्लादेश और चीन से लगी सीमाओं पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ने वाले असर को लेकर नई दिल्ली में चिंताएं बढ़ गई हैं। म्यांमार में भारतीय दूतावास

ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डोभाल बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो शुक्रवार को नेपीता में हो रही है।

भारतीय दूतावास ने कहा कि उन्होंने म्यांमार के एनएसए एडमिरल मो आंग से मुलाकात की, और बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों ने प्रधान मंत्री वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। डोभाल की अपने म्यांमार समकक्ष के साथ बैठक में म्यांमार में सुरक्षा स्थिति के बारे में भारत की चिंताओं पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष ने म्यांमार में हिंसा और अस्थिरता का भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव को उठाया।

नाटो देशों की तरह भारत को टेक्नोलॉजी और हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका

वॉशिंगटन (एजेंसी)। वॉशिंगटन(ईएमएस)। बीते रोज अमेरिकी सीनेट में लाए गए विधेयक में कहा गया है कि भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका को तत्पर रहने की जरुरत है। पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद और चीन से जुड़े सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर भारत का सहयोग करना चाहिए। साथ ही प्रस्तावित विधेयक में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को भारत के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ करता है। जिस तरह अमेरिका नाटो के सहयोगियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उनकी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं ठीक वैसे ही हमें भारत के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद रुबियो ने कहा,कम्युनिस्ट चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति से इंडो पैसेफिक में अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन की इन हरकतों को सुधारने के लिए हमें भारत के साथ-साथ अपने सभी सहयोगियों की हरसंभव मदद करने की जरूरत है।

रुबियो द्वारा लाया गया यह बिल भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है लेकिन इस समय अमेरिका में चुनावी महौल है। समय की कमी और कांग्रेस के आपसी विभाजन के कारण इस विधेयक के आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। लेकिन इस बात से यह साफ है कि अमेरिका की दोनों पार्टियां भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने को महत्व देती हैं। ऐसे में इस बिल को अगली कांग्रेस में फिर से पेश किया जा सकता है। विधेयक में कहा गया कि कम्युनिस्ट चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमें अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ अपने रणनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस विधेयक के अनुसार, अमेरिका भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए बढ़ते खतरों के जवाब में उसका समर्थन करेगा। और भारत के विरोधियों को रोकने के लिए भारत की हर संभव मदद भी करेगा इसके साथ ही वह अमेरिका रक्षा,नागरिक अंतरिक्ष के संबंध में भारत के साथ सहयोग करेगा।

पाकिस्तान को इस मामले में दो टूक कह देंगे कि यदि वह भारत के खिलाफ किसी भी तरह के आतंक में शामिल होता है तो उसको मिल रही तमाम सहायता और सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यह पहली बार है जब अमेरिकी कांग्रेस में इस तरीके का भारत-केंद्रित विधेयक पेश किया गया हो, जिसमें भारत को अपने नाटो सहयोगी के स्थान पर रखने और काट्सा प्रतिबंधों से छूट देने और भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध की बात कही गई हो।

इस कानून के पारित होने के बाद, यह भारत को रूसी सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए सीएएटीएसए प्रतिबंधों से एक सीमित छूट प्रदान करेगा जो वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जल्दी से जल्दी भारत की जरूरतों के हिसाब से

सैन्य हथियार और सेवाओं को तैयार करने में और उनकों भारत तक पहुंचाने में अपनी भूमिका को निभाएगा। विधेयक के अनुसार यह अमेरिका के हित में हैं कि भारत के पास खतरों को रोकने की आवश्यक क्षमताएं हों। इस लिए भारत के साथ भी नाटो सहयोगियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसमें साथी देशों को हथियारों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी प्रदान की जाती है। भारत के साथ एक समझौता किया जाए और उसे दो वर्षों के लिए अतिरिक्त सैन्य सामग्री देना चाहिए।